साप्ताहिक
# शांति मिशन
नई दिल्ली

वर्ष-29 अंक- 06 06-12 फरवरी 2022 पृष्ठ 12

अन्दर पढ़िए

जलवायु परिवर्तन तथा अर्थव्यवस्था को लेकर हमें जल्द पछताना पड़ेगा
पृष्ठ-6

नशाखोरी एक ख़तरनाक बीमारी
पृष्ठ-7

## संविधान में दिए गए अल्पसंख्यकों के अधिकार का हनन और धर्म संसदों में मुसलमानों के नरसंहार का ऐलान करने वालों के विरुद्ध

# प्रधानमंत्री की चुप्पी

## भारतीय लोकतंत्र का खुला मज़ाक

**इंडियन मुस्लिम्स फॉर सेकुलर एंड डेमोक्रेसी ने हरिद्वार में होने वाली धर्म संसद में भारतीय मुसलमानों के नरसंहार की अपील पर प्रधानमंत्री की चुप्पी को जनतंत्र का खुला मज़ाक बताते हुए यह प्रश्न सही किया है कि हिन्दुस्तान और विश्व के मुसलमानों को आख़िर वह क्या संदेश देना चाहेंगे।**

हमने अभी कुछ दिन पहले ही अपना 73वां गणतंत्र दिवस मनाया है। हालांकि कोविड-19 की वजह से यह पूर्व अपने पूरे साज-सज्जा के साथ तो नहीं मनाया गया मगर फिर भी इस राष्ट्रीय पर्व पर हमने कोविड प्रोटोकॉल के साथ खुशियों का इज़हार करते हुए इस कौमी पूर्व को मनाया। 15 अगस्त की यौमे आज़ादी और 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस हमें इस बात का अवसर देते हैं कि हम अपनी आज़ादी और जम्हूरियत की इन क़दरों का कमअज़कम एक सरसरी जाएज़ा लें, जिनको प्राप्त करने के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने खून के दरिया पार किए थे और जिनको बाक़ी रखने और परवान चढ़ाने हमारे सत्तापक्ष इन अवसरों पर अहद करते हैं।

यह एक हक़ीक़त है कि हमारी आज़ादी और लोकतंत्र हमारे संविधान की 'रक्षा' उस पर अमल करने में छुपा है इसलिए कि क़ानून की कोई पुस्तक चाहे कितनी ही ख़ूबसूरत गिलाफ में लिपटी हुई हो और चाहे उसे सोने की क़लम से लिखा गया हो, अगर उस पर अमल नहीं होगा तो उसकी कोई भी हैसियत नहीं हो सकती, हम 14, नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं और अपने संविधान की अच्छाईयों का बखान करते है। यह ही वह संविधान है जिसकी क़सम खाकर हमारे शासक पद प्राप्त करते हैं इसके साथ ही 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक दिवस मनाकर हमारे शासक अल्पसंख्यकों को यक़ीन दिलाते हैं कि भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को दिए गए अधिकार के रखवाले और रक्षक हैं। यहां अहम प्रश्न यह है कि क्या हमारे सत्तारूढ़ दल संविधान की रक्षा के लिए जो शपथ लेते हैं आख़िर उस पर अमल कितना करते हैं। इस समय भारत जिन परिस्थितियों से गुज़र रहा है उनको देखें तो जवाब नकारात्मक ही आएगा इसलिए कि आप जिस ओर भी नज़र डालेंगे आप को संविधान की धज्जियां ही उड़ी दिखाई देगी।

संविधान में दर्ज नागरिकों के बुनियादी अधिकार का खुलेआम सरकारी संस्थाओं में मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है। इस मज़ाक उड़ाने में मीडिया उनका साथ दे रहा है और न्यायालय मुस्कुरा रहा है। संविधान में दर्ज धार्मिक स्वतंत्रता का जनाज़ा निकला गया है। दाढ़ी, टोपी और नकाब पर तंज़ कसे जा रहे हैं। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा का खेल खेला जा रहा है। लव जेहाद के नाम पर पसंद की शादी मज़हब परिवर्तन के विरुद्ध एक्ट बनाए जा रहे हैं। अपने धर्म के प्रचार की आज़ादी का प्रयोग करने वाले जेलों में बंद किए जा रहे हैं, अपने अधिकार की आवाज़ उठाने वालों को गोलियों का निशाना बनाया जा रहा है। बीफ के नाम पर फ्रीज और किचन की तलाशी ली जा रही है। बुली बाई ऐप के माध्यम से मुस्लिम महिलाओं की आबरू को उछाला जा रहा है, घुसपैठियों की खोज में एक विशेष धर्म के नागरिकों को देश निकाला करने की योजना बनाई जा रही है जिसका साफ मतलब यह है कि संविधान में दर्ज तमाम बुनियादी अधिकार दांव पर हैं। न आप अपनी मर्ज़ी से खा सकते हैं न अपनी मर्ज़ी का धर्म अपना सकते हैं न अपनी पसंद की शादी कर सकते हैं, यह इस समय हमारे प्यारे वतन की सूरतेहाल है।

लोकतंत्र का एक खम्बा मीडिया है जिसका 90 प्रतिशत हिस्सा भगवा हो गया है। तमाम बड़े अख़बारों और इलेक्ट्रॉनिक चैनलस के मालिकान फासिस्ट नज़रियात के गुलाम हैं। इस मीडिया का काम सरकार के लिए माहौल बनाना और विपक्ष को बदनाम करना बल्कि मज़ाक़ उड़ाना हैं। टी. वी. चैनल्स पर होने वाले डिबेट ग़ैर संजीदा होते हैं। जिसमें शामिल होने वाले नुमाइंदों की भाषा अव्यवहारिक होती है और वह जिस मौज़ू को उठाना चाहिए उस पर बहस न करके भटकाने वाला प्रचार करते दिखते हैं। केवल टीआरपी की खातिर यह सब होना एक आम बात हो गई है। सोशल मीडिया भी बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ रहा है और हैरत की बात यह है कि हमारे प्रशासक खासतौर पर हमारे प्रधानमंत्री जो हर महीने 'मन की बात' जनता के सामने करते है और अपने 'मन की बात' जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते है, प्रधानमंत्री जी की संविधान में दिए गए अलपसंख्यकों के अधिकारों के अधिकारों और हनन और धर्म संसदों में मुसलमानों के नरसंहार की आवाज़ ऊंची करने वालों के विरुद्ध चुप्पी एक नए मायने और नए शंका को जन्म दे रहा है। देश का सहिष्णु वर्ग यह सोचने लगा है कि प्रधानमंत्री की इस चुप्पी के पीछे आख़िर क्या राज़ है। देश के विभिन्न वर्गों की ओर से इन हालात के विरुद्ध बराबर आवाज़ें उठ रहीं हैं मगर हमारे

बाक़ी पेज 11 पर

### भास्कर एनालिसिस - पिछले चार साल से लगातर बढ़ रही बेरोज़गारी

## देश में 3.03 करोड़ युवा बेरोज़गार, ये लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा

रेलवे की परीक्षा में गड़बड़ी के बाद युवा प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन, क्या सिर्फ एक परीक्षा में हुई गड़बड़ी से ही युवा इतने नाराज़ हैं? जानकारों की मानें तो युवाओं में गुस्से की बड़ी वजह बेरोज़गारी का रिकॉर्ड स्तर हैं बेरोज़गारी का डेटा जारी करने वाली संस्था सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी (सीएमआईई) के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर-दिसंबर 2021 के दौरान देश में बेरोज़गारों की कुल संख्या 3.18 करोड़ रही। इसमें 3.03 करोड़ 29 साल से कम आयु के हैं। यह संख्या 2020 में देशभर में लगे लॉकडाउन के दौर से भी ज़्यादा है। तब देश में 2.93 करोड़ युवा बेरोज़गार थे। 3.03 करोड़ युवा तो वे हैं, जो सक्रियता से काम खोज रहे हैं। 1.24 करोड़ युवा ऐसे भी हैं, जो रोज़गार तो चाहते हैं, लेकिन सक्रियता से काम नहीं खोज रहे। यदि इन्हें भी शामिल कर लें तो युवा बेरोज़गारों की संख्या 4.27 करोड़ हो जाती है।

सीएमआईई बेरोज़गारी का डेटा जारी करने वाली एकमात्र संस्था है। सीएमआईई के डेटा का इस्तेमाल आरबीआई समेत केन्द्र सरकार के विभाग भी करते हैं। युवाओं में बेरोज़गारी का एक बड़ा कारण नई नौकरियां पैदा न होना है, इसलिए ज़्यादा युवा बेरोज़गार हैं। कम पढ़ा लिखा छोटा मोटा काम शुरू कर देता है, लेकिन, शिक्षित युवा योग्यता के अनुरूप ही नौकरी तलाशते हैं। लंबे समय तक काम की तलाश के बाद भी वंचित रह गए बहुत से लोग निराश हो चुके हैं वे अब नौकरी तलाशने भी नहीं आ रहे। बेरोज़गारी बढ़ने का एक कारण कुछ सालों से अर्थव्यवस्था संतुलित तरीके से नहीं बढ़ी, यही प्रमुख कारण है। कंस्ट्रक्शन, टूरिज्म, हॉस्पिटेलिटी जैसे सेक्टरों का बिजनेस अर्थव्यवस्था की रफ्तार के मुकाबले कम बढ़ा है।

# धधकते कजाकिस्तान के लिए क्या है आगे का रास्ता

कजाकिस्तान के पिछले तीस सालों के इतिहास का यह सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है। दुनिया के कुल यूरेनियम उत्पादन का 40 फसदी कजाकिस्तान से आता है। कजाकिस्तान में हो रही उथल पुथल, अस्थिरता भारत के लिए भी चिंताजनक है। कजाकिस्तान धधक रहा है। कजाकिस्तान की सड़कों पर अचानक भड़के हिंसक प्रदर्शन, सरकार द्वारा उन्हें सख़्ती से दबाना, महंगाई की मार से त्रस्त आमजनों के बीच ज़िन्दगी को चलाने की दहशत, अराजक प्रशासकीय स्थिति से निपटने के लिए देश के शीर्ष नेतृत्व द्वारा रूसी सेना को बुलाया जाना - कजास्तिान से इन दिनों ऐसी ही चिंताजनक ख़बरें आ रही हैं।

ईंधन की बेशुमार बढ़ती कीमतों, महंगाई और अराजक प्रशासकीय स्थिति व सरकार की निरंकुश नीतियों के विरोध में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन अब देश की भावी तस्वीर बदलने के जनांदोलन का रूप लेता जा रहा है। कजाकिस्तान के पिछले तीस सालों के इतिहास का यह सबसे बड़ा राजनीतिक संकट है, जिसका क्या हल निकलेगा, कजाकिस्तान के लिए आगे का रास्ता क्या होगा, यह एक बड़ा प्रश्न है। आख़िर कजाकिस्तान क्यों उबल रहा है? यूरेनियम के समृद्ध विपुल प्राकृतिक भंडारों के स्रोत वाले कजाकिस्तान की इस अफरा-तफरी और दहशतभरी ख़बरों के बीच याद आता है कि कुछ बरस पहले का कजाकिस्तान, जब विदेश मंत्रियों की एक अहम बैठक में कजाकिस्तान के शांत और ख़ूबसूरत अलमाटी शहर जाने का मौक़ा मिला।

प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित एक बेहद ख़ूबसूरत, गर्मजोशी रखने वाले बेफिक्र से समृद्ध लोगों का देश। भारतीय सैलानियों के लिए भी कजाकिस्तान एक पसंदीदा पर्यटक स्थल के रूप में उभर रहा था। दुनिया के कुल यूरेनियम उत्पादन का 40 फीसदी कजाकिस्तान से आता है जो परमाणु संयंत्रों के लिए मुख्य ईंधन है। इसलिए यहां उत्पन्न सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। कजाकिस्तान में हो रही उथल-पुथल, अस्थिरता भारत के लिए भी चिंताजनक है।

**निश्चित ही मध्य एशिया में हो रही अस्थिरता भारत के लिए प्रतिकूल है। कजाकिस्तान की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि रूस के साथ-साथ चीन, अमेरिका सभी महाशक्तियों की निगाहें यहां के घटनाक्रम पर लगी है। कजाक हिंसक प्रदर्शनों के बाद चीन ने वहां सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है।**

पिछले कुछ सालों से भारत मध्य एशियाई देशों के साथ मज़बूत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कहा है कि एक निकट और साझीदार मित्र होने के नाते वह वहां हालात के जल्द स्थिर होने का इंतज़ार कर रहा है तथा वहां गए भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को लेकर स्थानीय प्रशासकीय अधिकारियों के समन्वय से काम कर रहा है।

निश्चित ही मध्य एशिया में हो रही अस्थिरता भारत के लिए प्रतिकूल है। कजाकिस्तान की अहमियत इसी बात से समझी जा सकती है कि रूस के साथ-साथ चीन, अमेरिका सभी महाशक्तियों की निगाहें यहां के घटनाक्रम पर लगी है। कजाक हिंसक प्रदर्शनों के बाद चीन ने वहां सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है। साथ ही चीन ने कजाकिस्तान में बाहरी ताक़तों द्वारा हस्तक्षेप का विरोध करने की भी बात कही है। चीन की कजाकिस्तान को लेकर इस तरह की सक्रियता भी अनेक प्रश्न उठा रही है। एक विशेषज्ञ के अनुसार चीन इस बात से आशंकित है कि अगर उसके पड़ोस में अशांति होगी तो उसका चीन के ऊर्जा व्यापार पर, बेल्ट एंड रोड परियोजना पर असर पड़ेगा। यानि आशंका यह भी है कि कजाकिस्तान अर्थ व्यवस्था को चीनी हाथों में धकेलने की संभावनाएं लिए हैं। इसके अलावा चीन को लगता है कि इसका असर उसके शिजिन्याग इलाके पर भी पड़ेगा, जो कजाकिस्तान के साथ 1770 किमी लंबी सीमा सांझा करता है। दरअसल मध्य एशिया की अस्थिरता एक स्थिर और समृद्धि की ओर बढ़ता देश रहा है। सालों तक बनी स्थिरता के चलते पिछले दो दशकों में संसाधनों के मामले में सम्पन्न इस देश की अर्थव्यवस्था कई गुना बढ़ी, लेकिन सरकार की श्रम नीतियों वगैरह को लेकर अंदर ही अंदर कुछ असंतोष तो था। कजाकिसतान की इन घटनाओं को बेलारूस, यूक्रेन और कजाकिस्तान में चल रही उथल पुथल से जोड़कर देखना होगा।

हालांकि इन सभी देशों में चल रही उथल-पुथल की अपनी अलग अलग वजहें हैं लेकिन विशेषज्ञ मानते

बाक़ी पेज 11 पर



# ढाई वर्ष में 10 हज़ार तक पहुंचेगा राजधानी का बस बेड़ा

दिल्ली में लोगों को ढाई वर्ष बाद बसों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। सार्वजनिक परिवहन के क्षेत्र में अगले दो सालों में दिल्ली की सूरत बदलने जा रही है। 2023 मध्य तक 2830 बसें आ जाएंगी और तब जनता के लिए कुल बसें उपलब्ध होगी 9724। खास बात यह है कि आने वाली कुल बसों में 2130 इलेक्ट्रिक और 700 बसें सीएनजी की होंगी। इसके लिए तैयारी शुरू हो चुकी है। दिल्ली में इस समय 6894 बसें सड़कों पर चल रही हैं।

अभी बसें लाए जाने की जो योजना है उसके तहत 250 सीएनजी बसें इस वर्ष मार्च-अप्रैल तक आएंगी। इसके अलावा 450 सीएनजी बसें अक्तूबर में अपनी हैं। 300 इलेक्ट्रिक बसों के टेंडर हो गए हैं। टाटा और जेबीएम कंपनियां भी निर्धारित हो गई हैं। बसें डीटीसी के बेड़े में शामिल होंगी। इनमें से जेबीएम की एक बस दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही है और 299 बसों में से 55 बसें 15 फरवरी तक आएंगी। कुल मिलाकर सभी 300 बसें अप्रैल तक आ जाएंगी। इसके अलावा क्लस्टर सेवा के तहत 330 इलेक्ट्रिक बसों के लिए भी टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ये बसें हर हाल में 2023 के मध्य तक आएंगी।

एक अलग व्यवस्था के तहत डीटीसी के लिए 1500 इलेक्ट्रिक बसें भी 2023 मध्य तक आ जाएंगी। इस व्यवस्था के तहत दिल्ली सरकार ये 15000 बसें केन्द्र सरकार की एजेंसी कन्वर्जेस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (सीईएसएल) से लेगी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने सीईएसएल के पास आवेदन भेज दिया है।

दरअसल सीईएसएल ने 130 डबल डेकर सहित 5580 इलेक्ट्रिक बसों की ख़रीद के लिए लगभग 5500 करोड़ रुपये की सबसे बड़ी निविदा निकाली है। सीईएसएल ने इनमें से दिल्ली सरकार को बसें उपलब्ध कराने का भरोसा दिया है।

वर्तमान में दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन के रूप में 6894 बसें चल रही हैं। इनमें अभी डीटीसी की 3761 बसें हैं। इसमें एक इलेक्ट्रिक बस भी शामिल हैं। क्लस्टर सेवा के तहत इस समय 3133 बसें चल रही हैं। दिल्ली में कोरोना महामारी के पहले तक बसों में प्रतिदिन 42 लाख लोग सफर करते रहे हैं और मेट्रो में 24 लाख लोग यात्रा करते हैं।

परिवहन मंत्री कैलाश गहलौत का कहना है कि दिल्ली का बस बेड़ा अभी तक का सबसे बड़ा बेड़ा है। नई बसें लाए जाने के लिए तेज़ी से काम चल रहा है। 2830 बसें हर हाल में 2023 के मध्य तक दिल्ली में आ जाएंगी। निजी बसों का संचालन कर रहे ऑपरेटर्स के संगठन एसटीए ऑपरेटर्स एकता मंच के महासचिव श्याम लाल गोला कहते हैं कि ढाई वर्ष में 2830 बसें लाना सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मगर इलेक्ट्रिक बसों के मामले में चुनौती ज़रूर हैं ऐसे में सरकार को इलेक्ट्रिी बसों के मामले में निजी बस संचालकों को भी साथ लेना चाहिए जो सरकार के साथ आने के लिए तैयार हैं। ❑❑

## 2021 में केवल 29 दिन ही स्वच्छ हवा ले सके हैं दिल्लीवासी

दिल्ली के 34 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों से जनवरी का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक मौसम (एक्यूआई) विभाग को मिल रहा है, वह गंभीर से बहुत ख़राब श्रेणी में दर्ज हो रहा है। राजधानी में 2020 के बाद जनवरी 2022 में सर्वाधिक वर्षा भी दिल्ली के वातावरण को सांस लेने योग्य स्वच्छ नहीं बना पा रही। राजधानी में रहने वाले लोगों को पूरे वर्ष में मिलने वाले कुल 2019 में 23 दिन, 2020 में 50 दिन व 2021 में मात्र 29 दिन रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति पर सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट के अविकल सोमवंशी कहते है। कि दिल्ली में एक बार फिर से पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 2020 के मुक़ाबले बढ़ गया है, जो कि चिंताजनक है। 2020 में जहां पीएम 2.5 का वार्षिक स्तर 97 हो गया था वह 2021 में बढ़कर 109 पहुंच गया है। पुराने आंकड़े में 12 अंक की बढ़ोत्तरी हुई है। ऐसे हालात जनवरी 2022 के पहले सप्ताह तक जारी रहे हैं जबकि यही पीएम 2.5 2019 में 110 के वार्षिक स्तर पर था। कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन ने इसमें 2020 में जो सुधार किया था, वह 2021 में बरकरार नहीं रह सका।

हालांकि दिल्ली में रहने वाले लोगों को 2021 में 2019 के मुक़ाबले प्रदूषण के अति गंभीर श्रेणी वाले कम दिनों का ही सामना करना पड़ा। 2019 में वातावरण अति गंभीर श्रेणी में वर्ष में 36 रहा था, वहीं 2021 में यह घटकर वर्ष में 27 दिन रहा। हालांकि लॉकडाउन के कारण 2020 में मात्र 20 दिन ही अति गंभीर श्रेणी में दर्ज किए गए थे। अविकल के मुताबिक, दिल्ली में नवंबर से जनवरी तक प्रतिवर्ष प्रदूषण बहुत ख़राब की श्रेणी में रहता है। फरवरी में इससे राहत मिलनी शुरू हो जाती है। 2021 में प्रदूषण के कारण बहुत खराब दिनों की संख्या में भी बीते सालों की अपेक्षा वृद्धि देखने को मिली है। 2019 में जहां मात्र 72 दिन ही बहुत ख़राब की श्रेणी में दर्ज थे, यह संख्या 2021 में बढ़कर 94 हो गई। सांस लेने योग्य अच्छे दिनों की संख्या में गिरावट हुई है, ये सभी अच्छे दिन भी मानसून के महीनों के बीच के ही रह गए हैं।

संपादकीय

# शांति मिशन

# बुली बाई

## घृणित मानिसकता या साज़िश

विवादास्पद 'बुली बाई' ऐप मामले में लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरहब प्लेटफार्म पर ऐप बनाने वाले 21 वर्ष के नीरज बिश्नोई को असम में गिरफ्तार कर उसे ही मास्टर माइंड माना है। नीरज बिश्नोई भोपाल के वेल्लौर इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी से कम्प्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रहा है। इस मामले में उत्तराखंड की 18 वर्ष की श्वेता सिंह, बेंगलुरु के 21 वर्षीय विशाल झा और 20 वर्षीय मयंक रावल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। श्वेता सिर्फ 12वीं पास और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रही थी। उसके कंधे पर दो बहनों और एक भाई की ज़िम्मेदारी है। उसकी मां की कैंसर से उसके पिता की कोरोना से मौत हो चुकी हैं। असम से पकड़े गए नीरब बिश्नोई के पिता एक दुकान चलाते हैं। लॉकडाउन के दौरान वह भोपाल से घर चला आया था। पूरे दिन वह अपने कमरे में बैठकर कम्प्यूटर में घुसा रहता था और देर रात तक काम करता था। कुछ राजनीतिक दलों के लोग भी उससे मिलने आते थे। उसकी दोनों बहनों को उसके काम पर शक भी हुआ तो वह झगड़ने लगता। पकड़े गए दो अन्य युवकों की आयु भी कोई ज़्यादा नहीं है। बुली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं को निशाने पर लेकर उनकी बोली तक लगाई जा रही थी। इस विवादित ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के चित्र अपलोड कर उनके बारे में अश्लील और अनुचित बातें लिखी गईं। इससे पहले भी पिछले वर्ष जुलाई में ऐसे ही विवादित ऐप सुन्नी बाई पर मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करने का मामला सामने आया था, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने पर उससे मिलता-जुलता ऐप सामने आ गया।

गिरहब एक होस्टिंग प्लेटफार्म है, इस प्लेटफार्म पर अलग-अलग तरह के ऐप मिल जाएंगे। गिरहब एक ओपन सोर्स प्लेटफार्म है, जो यूजर्स को ऐप्स बनाने और साझा करने की अनुमति देता है। इसके लिए आपको ई-मेल की ज़रूरत पड़ती है। बुली बाई ऐप पर मुस्लिम महिलाओं के मानसिक उत्पीड़तन का मामला तब सामने आया जब एक महिला पत्रकार ने टवीटर पर अपनी आपबीती साझा की। इस ऐप के डेवलेप करने वाले लोगों ने इस महिला पत्रकार की फोटो ऐप पर शेयर कर दी थी। लोग उनकी फोटो पर अश्लील कमेंट लिख रहे थे। इस ऐप पर लगभग सौ महिलाओं को टारगेट किया गया।

अब प्रश्न यह उठता है कि क्या पकड़े गए युवाओं की मानसिकता घृणित है या उन्हें इस काम के लिए बरगलाया गया है। साइबर वर्ल्ड ने दुनिया को प्रगति का रास्ता ज़रूर दिखाया है लेकिन यह घृणित मानसिकता वालों और अपराधियों के घातक मंसूबों को अंजाम देने का हथियार बन चुका है। प्रश्न यह भी है कि पकड़े गए युवकों को क्या इस बात का एहसास नहीं था कि ऐसा करने पर सामाजिकता ताना-बाना छिन्न भिन्न हो सकता है। क्या उन्हें इस बात की समझ नहीं थी कि इससे समाज में कटुता और विद्वेष फैल सकता है, जिसके परिणामस्वरूप हिंसा हो सकती है। आख़िर छोटी आयु में बड़ा कांड करने की सोच उनके पास कहां से आई। अगर उन्हें किसी ने गुमराह नहीं किया तो यह हमारे समाज के लिए बहुत घातक है कि हमारे युवा किस मानसिकता का शिकार हो रहे हैं। उत्तराखंड से पकड़ी गई 18 वर्षीय श्वेता में इतनी नफ़रत कैसे आ गई? कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र नीरज में आपराधिक कारनामा करने का साहस कैसे आया.?

इसमें कोई संदेह नहीं कि समाज में साम्प्रदायिक ज़हर फैलाने, आतंकवादी घटनाओं के लिए युवाओं को भर्ती करने वाले, धर्म के नाम पर युवाओं का माइंडवॉश करने वाले संगठन और उनके स्लीपर सेल अपने नापाक इरादों को अंजाम देने के लिए उन युवाओं का इस्तेमाल करते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं। गिरफ्तार युवकों की पारिवारिक पृष्ठभूमि का तो ब्यौरा मिल चुका है, लेकिन इस मामले की तह तक जाना ज़रूरी है। यह देखा जाना ज़रूरी है कि किन हालातों में युवा इस ऐप से जुड़े, क्या पर्दे के पीछे से इन्हें कोई इस्तेमाल कर रहा था। अगर यह साज़िश है तो फिर असली किरदारों के चेहरे से नक़ाब उतरना ही चाहिए। किशोरों और युवाओं को मोहरा बनाकर कौन साम्प्रदायिक विद्वेष फैला रहा है।

बुली बाई ऐप ने जितना समाज में नुकसान कर दिया है, उसकी भरपाई आसान नहीं है। इसका एक पहलू यह भी है कि इस ऐप के ज़रिये हिन्दुओं को बदनाम करने की साज़िश रची गई। गिरफ्तार युवाओं को क़ानून के मुताबिक़ सज़ा भी मिल जाएगी लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि समाज को ऐसी ज़हरीली सोच से बाहर कैसे निकाला जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो सामाजिक समरसता का ख़तरा उत्पन्न हो सकता है। ज़रूरत इस बात की है कि समाज में नफ़रत फैलाने वाले साइबर अपराधियों पर नकेल कसी जाए।

दरअसल दुनियाभर में साइबर स्पेस तेजी से यौन विकृतियों, आर्थिक अपराधों, आतंकवादी गिरोहों और महिलाओं को निशाने पर लेने वाले ट्रोलर्स का अड्डा बनता जा रहा है। भारत इससे अछूता कैसे रह सकता है। पिछले वर्ष देश में महिलाओं के ख़िलाफ़ साइबर अपराध के लगभग 2300 मामले सामने आए थे। इनमें से अधिकतर अपराध यसौन सामग्री के प्रकाशन और प्रसारण से जुड़े थे। समाज में बढ़ते मोबाईल फोन के बढ़ते उपयोग और इंटरनेट के दायरे के विस्तार ने महिलाओं को यौन उत्पीड़न की दृष्टि से बहुत संवेदनशील बना दिया है। महिला किसी भी समुदाय की क्यों न हो, ऐसे हमलों की शिकार नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आईटी संशोधन अधिनियम को और भी सख़्त बनाया जाना चाहिए।❑❑

# नबी-ए-पाक सल्लाहुअलैहि वसल्लम की ज़िन्दगी

कुछ इतिहासकारों के अनुसार आपको नबूवत इतवार के दिन अता हुई लेकिन महीना के बार में इतिहासकारों का मतभेद है। इब्ने अब्दुल बर के अनुसार आठ रबीउल अव्वल को नबूवत से सुशोभित हुए। इस कथन के आधार पर उस समय आपकी उम्र चालीस वर्ष थी जबकि अब्ने इस्हाक़ के कथन के अनुसार 17 रमज़ान को आपको नबूवत मिली, इस कथन के अनुसार बवक़्त बेसत आपकी उम्र चालीस वर्ष और छह महीने थी, हाफिज़ इब्ने हज्र ने इसी कथन को वरीयता दी है।

(फतह अल बारी, किताब अल ताबीर 12/313)

नबूवत के दूसरे वर्ष में आप (सल्ल॰) गुप्त तब्लीग़ (प्रचार- प्रसार) फरमाते रहे। इसी वर्ष हज़रत खदीजा, हज़रत वरक़ा बिन नाफिल, हज़रत अली अल मुर्तजा, हज़रत अबू बक़र सिद्दिक, हज़रत जाफर बिन अबी तालिब, हज़रत अफीफ कन्दी, हज़रत तल्हा, हज़रत सअद बिन अबी वकास, हज़रत खालिद बिन सईद, हज़रत उस्मान बिन अफ्फान, हज़रत अम्मार, हज़रत सुहेब, हज़रत उमरू बिन अन्बसाह और ज़ैदइ बिन हारिसा रज़ि॰ अल्लाह अन्हुम अजमईन आप (सल्ल॰) पर ईमान लाए, यह सब और कुछ दूसरे हज़रात सहाबा पहले और बाद के सहाबा कहलाते हैं। नबूवत के तीसरे वर्ष आप (सल्ल॰) के मतबना हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ि॰ अल्लाह के बेटे हज़रत ओसामा की पैदाइश हुई।

नबूवत के चौथे वर्ष आप (सल्ल॰) को खुलेआम दीन की दावत देने का आदेश हुआ जिसके आधार पर कुफ़्फार विशेषकर कुरैश की तरफ से भी खुल्लम खुल्ला दुश्मनी और बुग्ज़ व अदावत का प्रदर्शन होने लगा और इसी वर्ष हज़रत आएशा रज़ि॰ अल्लाह अन्हा की पैदाइश हुई।

नबूवत के पांचवें साल हज़रत जाफर बिन अबी तालिब रज़ि॰ अल्लाह अन्हा इस्लाम में शामिल हुए, इसी वर्ष हब्शा की तरफ पहली और दूसरी हिजरत हुई, पहली हिजरत में 11 पुरुष और पांच औरतें शामिल थीं (फतेह अल बारी 1/80) और दूसरी हिजरत में 85 पुरुष और 16 औरतें शामिल थीं (सीरत इब्ने हिशाम 1/111)। इसी वर्ष हज़रत समीहा रज़ि॰ अल्लाह अन्हा को अबू जहल मलऊन के हाथों शहाइद नसीब हुई, यह इस्लाम की ख़ातिर शहीद होने वाली पहली ख़ातून (महिला) हैं। नबूवत के छठे साल हज़रत हमज़ा और हज़रत उमर रज़ि॰ अल्लाह अन्हा इस्लाम में दाख़िल हुए और उनकी बरकत से मस्जिद हराम में नमाज़ खुले तौर से अदा की गयी। (शरह अल मवाहिब 1/276)

नबूवत के सातवें वर्ष मकातआ कुरैश का वाक्या पेश आया, आप (सल्ल॰) अलैहिस्सलाम के साथ बनू हाशिम और बनू मुत्तलिब शअब अबी तालिब में महसूर क़ैद कर दिए गए, इसी दौरान आप (सल्ल॰) के चचाज़ाद भाई अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि. अन्हुमा की पैदाइश हुई।

(रोज़ अल अनफ 1/232)

नबूवत के आठवें वर्ष मक्का के मुशरीकिन की मांग पर शिक क़मर का बेमिसाल मोअज्ज़ा सामने आया। (अल बदायह व अल निहाया 3/118)

नबूवत के नवें वर्ष में भी शअब अबी तालिब में ही कैद रहें

नबूवत के दसवें वर्ष मकातआ ख़त्म हुआ (तबकात इब्ने सअद 1/139) और इसी वर्ष आप (सल्ल॰) के चचा अबू तालिब का इंतेक़ाल हुआ इनके इंतेक़ाल के लगभग तीन या पांच दिन बाद हज़रत खदीजा रज़ि अल्लाह अन्हा का इन्तेक़ाल हुआ, हुजूर (सल्ल॰) ने इस वर्ष को आम अल हज़न करार दिया (शरह अल मवाहिब 1/291) इसी वर्ष आप (सल्ल॰) का निकाह हज़रत सौदा बिन्त ज़मीहा रज़ि अल्लाह अन्हा से हुआ और इसी वर्ष हज़रत आएशा रजि. अल्लाह अन्हा आप (सल्ल॰) के निकाह में आईं लेकिन रुखसती नहीं हुई। और इसी वर्ष वाक्या तायफ भी पेश आया।

(अल बदाया व अल निहाया 3/135)

नबूवत के 11वें वर्ष मदीना से आने वाले हाजियों में से आप (सल्ल॰) की दावत (निमंत्रण) से लगभगछह आदमी इस्लाम धर्म में शामिल हुए। इस से अंसार के इस्लाम का आगाज़ा हुआ।

(अल बदाया व अल निहाया 3/148)

नबूवत के 12वें वर्ष आप (सल्ल॰) को मेराज हुई और इसी अवसर पर उम्मत पर पांच नमाज़ें फर्ज़ हुईं। इसी वर्ष बेअत अक्बा अवला हुई इसमें 12 लोग इस्लाम में शामिल हुए। (शरह अल मवाहिब 1/316)

# समान सोच वाली पार्टियाँ पहले साथ आएं विपक्ष का नेता तो चुनाव बाद भी चुन लेंगे

## तेजस्वी यादव

**लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत के उत्तराधिकारी और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का मानना है कि 2024 का चुनाव मोदी के ख़िलाफ जनता लड़ रही होगी। ऐसे में उनके ख़िलाफ़ विपक्ष का चेहरा कौन होगा, इस पर अभी से बहस बेमानी है। चिराग़ पासवान को साथ लेने के प्रश्न पर उनका कहना है कि यह चिराग़ पासवान पर निर्भर है कि वह अपने पिता की राजनीतिक विरासत को कैसे संजोना और बचाना चाहते हैं। पेश है प्रादेशिक और राष्ट्रीय राजनीति से विभिन्न मुद्दों पर तेजस्वी यादव से हुई एक बातचीत के प्रमुख अंश**

**सवाल:**- बिहार के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य को आप किस रूप में देखते हैं?

**जवाब:**- हम कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। खींचतान और सत्ता लोलुपता से बिहार का नुकसान हो रहा है। अब सत्तासीन दलों के विधायक, मंत्री भी जनता की नब्ज़ को समझकर विद्रोह करने की तैयारी में हैं। पिछले दिनों सरकार के ही एक मंत्री ने भ्रष्टाचार और बेलगाम अफसरशाही से तंग आकर इस्तीफा देने का ऐलान किया। कोरोना की दूसरी लहर में पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे राज्य सरकार ने जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया।

**सवाल:**- चिराग़ पासवान से आपकी नज़दीकी बढ़ने की बात कही जा रही है। क्या चिराग़ को आप अपने गठबंधन में लेना चाहेंगे?

**जवाब:**- रामविलास पासवान जी से हम लोगों का दशकों पुराना पारिवारिक संबंध रहा है। कुल कालखंडों को छोड़ लालू जी और पासवान जी ने एक साथ राजनीति भी की है। उनकी मृतयु के पश्चात् जिस तरीके से भाजपा और नीतीश जी ने विश्वासघात किया है, उससे हम सभी आहत है। अब चिराग़ जी को तय करना है कि वह अपने पिता की विरासत को कैसे संजोना और आगे बढ़ाना चाहते हैं।

**सवाल:**- वैसे एलजेपी की टूट का बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ने की संभावना है

**जवाब:**- एलजेपी तो तोड़ने के अनैतिक कार्य में जो लोग या पार्टियां संलिप्त है, उनके ख़िलाफ़ आक्रोश का माहौल है। जनता समझ चुकी है कि नीतीश जी और मोदी/शाह की जोड़ी को सिर्फ सत्ता की भूख है और इसकी प्राप्ति के लिए वे लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। भाजपा-जे डीयू के साथ जो छोटे दल सरकार में शामिल हैं, वे पहले तो सिर्फ अपनी उपेक्षा से पीड़ित थे, अब वे अपने दल के भविष्य को लेकर आशंकित हैं।

**सवाल:**- आप पर बड़ा आरोप यह है कि बिहार को जब आपकी ज़रूरत होती है, तब आप वहां होते ही नहीं है?

**जवाब:**- यह आरोप सत्ता में बैठे वे लोग लगा रहे हैं जो अपनी ज़िम्मेदारी का निर्वह्न करने में असफल रहे हैं। मुख्यमंत्री कोरोना काल में खुद 143 दिनों तक अपने आवास से बाहर ही नहीं निकले। हम जनता की सेवा के लिए निकले तो हम पर आधे दर्जन केस लाद दिए। विपक्ष का नेता होने के नाते जनता मुझसे जो अपेक्षा करती है, मैं उसको पूरा कर रहा हूं। सबको मालूम है कि मेरे पिता बीमार हैं। इसी सिलसिले में मैं दिल्ली में था

**सवाल:**-राष्ट्रीय राजनीति की बात की जाए तो 2024 के मद्देनज़र आप विपक्ष को कितना तैयार देखते हैं?

**जवाब:**- मोदी सरकार की लगभग सभी नतियां जनविरोधी और देशविरोधी हैं। संख्या बल की बदौलत सरकार तानाशाही कर रही हैं। पिछले सात साल में मोदी सरकार ने अपने चुनावी वादों को जुमला साबित करने के अलावा कोई बड़ा कार्य नहीं किया है। 2024 में निश्चित रूप से ग़ैर भाजपा सरकार बनेगी।

**सवाल:**- राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा के ख़िलाफ़ गोलबंदी के लिए मुख्य विपक्षी दल होने के कांग्रेस को जो रोल निभाना चाहिए था, क्या वह निभा पा रही हैं?

**जवाब:**- मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि कांग्रेस समेत सभी समान विचारधारा वाली पार्टियों को अपनी छोटी बड़ी महत्वकांक्षाओं को त्यागकर देश को बचाने के लिए सार्थक प्रयास करना होगा। साझा लड़ाई में हम से और हमारी पार्टी से जो भी सहयोग और कुर्बानी की अपेक्षा जनता और सहयोगी दल करते हैं, उसके लिए हम तैयार हैं।

**सवाल:**- 2024 का चुनाव मोदी के ख़िलाफ़ विपक्ष को चेहरा घोषित करके लड़ना चाहिए या बग़ैर चेहरे के?

**जवाब:**- ये सब निरर्थक बाते हैं। 2024 का आम चुनाव के ख़िलाफ़ जनता लड़ रही होगी। अभी हमारा ध्येय इस जनविरोधी सरकार को हटाने पर है। प्रधानमंत्री कौन होगा, यह हम सभी लोग बैठ कर तय कर लेंगे।

**सवाल:**- मोदी के ख़िलाफ़ विपक्ष के किस नेता को आप बेहतर चेहरा मानते हैं?

**जवाब:**- शायद भाजपा में नेताओं का अकाल है, विपक्ष में ऐसा नहीं हैं। देश में एक से बढ़कर एक सुयोग्य, अनुभवी और काबिल नेता है। वक़्त आने पर इसका इसका जवाब मिल जाएगा।

**सवाल:**- अगले वर्ष की शुरुआत में यूपी सहित पांच राज्यों के चुनाव हैं, उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी?

**जवाब:**- उत्तर प्रदेश समेत जहां भी चुनाव हो रहे हें, हम कोशिश करेंगे कि भाजपा के जन विरोधी चरित्र को उजागर करें और धार्मिक उन्माद पैदा करने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने के सामूहिक प्रयास में सहभागी बनें। ❑❑

# जनहित में बोलने से कौन रोकेगा मुझे

## वरुण गांधी

**इन दिनों भाजपा सांसद वरुण गांधी सुर्ख़ियों में हैं। लगातार अपने बयानों के ज़रिए अपनी ही सरकार से प्रश्न कर रहे हैं। किसान आंदोलन की बात हो या युवाओं से जुड़े मसले, इनके सवालों ने सुर्खी तो बटोरी ही, अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। वरुण गांधी से विपक्ष को भी ताक़त मिल रही है। उनके सवाल उठाने के पीछे क्या है उनकी मंशा, क्या वह पार्टी की किसी रणनीति के तहत ऐसा कर रहे हैं, भविष्य में उनका क्या सियासी रास्ता हो सकता है, पेश है इन सब पहलुओं पर पेश है वरुण गांधी से हुई बातचीत के प्रमुख अंश।**

**प्रश्न:**- आजकल आप लगातार किसानों और युवाओं से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, एक स्वतंत्र आवाज़ के रूप में। इसे किस रूप में देखा जाए?

**उत्तर:**- जनता ने मुझे अपने मुद्दे उठाने के लिए ही सांसद चुना है। यह मेरा लोकतांत्रिक कर्तव्य है कि मैं जनता के विषयों पर बोलूं। यदि जनता की समस्याओं को मैं नहीं उठाऊंगा तो फिर चुनाव लड़ने, सांसद बनने या राजनीति करने के कोई मायने नहीं हैं।

**प्रश्न:**- पार्टी लाइन से हटकर कुछ बोलने में आपको डर नहीं लगता है? आपकी पार्टी नेतृतव से कोई संवाद हुआ?

**उत्तर:**- देखिए, मैं किसी डर या व्यक्तिगत लाभ-हानि की दृष्टि से राजनीति नहीं करता। यदि जनसरोकार के मुद्दों को उठा नहीं सकता तो ऐसी राजनीति का कोई अर्थ नहीं है। जनता के हित में बोलता हूं तो कौन रोकेगा, कौन टोकेगा? पार्टी में संवाद तो होता रहता है। मेरे विचारों को मानने से पार्टी को लाभ ही होगा।

**प्रश्न:**- आप उत्तर प्रदेश से सांसद हैं। आपने अलग अलग मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी। क्या कभी उसका जवाब आया..?

**उत्तर:**- जवाब से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उन मुद्दों का उपयुक्त हल निकलना चाहिए।

**प्रश्न:**- क्या पांच राज्यों के चुनावों में युवा, किसानों की नाराज़गी या महंगाई का असर देखा जा सकता है?

**उत्तर:**- जनता के मुद्दों का असर चुनाव पर पड़ता तो है परंतु केवल कुछ मुद्दों के आधार पर ही चुनाव में हार-जीत होती है यह कहना भी ठीक नहीं है। मुद्दों का असर तो पड़ेगा परंतु किस मुद्दे का कितना असर होगा, यह कहना बहुत मुश्किल है।

**प्रश्न:**- वैसे आपकी नज़र में देश की तीन सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं?

उत्तर:- किसानों को फसलों की उचित और लाभकारी कीमत नहीं मिल रही, लागत बढ़ रही हैं, खेती घाटे का सौदा बन चुकी है, अत: युवा खेती नहीं करना चाहते। दूसरे, बेरोज़गारी बहुत बड़ी समस्या है। बेरोज़गार युवाओं को उचित रोज़गार उपलब्ध करवाना, उनकी ऊर्जा को सकारात्मक रूप से देशहित में उपयोग करना देश के भविष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। तीसरे, अर्थव्यवस्था अलग-अलग कारणों से बहुत ख़राब स्थिति में हैं जिसका दुष्परिणाम महंगाई, बेरोज़गारी आदि के रूप में सामने आ रहा है।

**प्रश्न:**- आपने किसानों के मसले पर एक किताब भी लिखी है। आपके हिसाब से तीनों कृषि क़ानूनों में कहां चूक रह गई?

**उत्तर:**- इन क़ानूनों में कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके कारण मंडी व्यवस्था बर्बाद हो सकती थी, कृषि एवं जिन्स व्यापार कुछ निजी कंपनियों के हाथों में सिमट सकता था। कालांतर में किसान और उपभोक्ता, दोनों का नुकसान होता और देश में रोटी बहुत महंगी हो जाती हैं।

**प्रश्न:**- वैसे देश की राजनीति किस दिशा में जाती दिख रही है..?

**उत्तर:**- सभी पार्टियां, सरकारें अपने-अपने तरीक़े और नीतियों से जनहित में काम करने का प्रयास करती हैं। जो जनता की नज़रों में खरा उतरता है, उसे जनता दोबारा मौक़ा देती है। जो ऐसा नहीं करते, उन्हें जनता चुनावों में बाहर कर देती है। मेरी राय से जनता की राय ज़्यादा मायने रखती है, जनता सबकी राजनीति को हर पांच साल में तोल देती है यही लोकतंत्र की ख़ूबसूरती है।

**प्रश्न:**- इन दिनों असल मुद्दों की जगह कई बार हेट या दूसरी चीजें अधिक हावी हो जा रही हैं गिरते डिस्कोर्स पर आप क्या कहना चाहेंगे?

**उत्तर:**- नकारात्मक विमर्श के लिए सभी ज़िम्मेदार हैं। सरकार, राजनीतिक दल, आम जनता और मीडिया सबकी ज़िम्मेदारी है। इसे रोकना होगा परंतु अभिव्यक्ति की आज़ादी भी प्रभावित नहीं होनी चाहिए।

**प्रश्न:**- आपने बैंकों के निजीकरण पर भी सवाल खड़े किए? क्या ख़तरे हैं इसके?

**उत्तर:**- निजीकरण हर मर्ज़ की दवा नहीं है। हमारे देश में मिली-जुली अर्थव्यवस्था है। बैंक स्वस्थ अर्थव्यवस्था का आधार है। निजीकरण से अर्थव्यवस्था और समान धन प्रवाह बाधित होगा। बैंकों तक आम आदमी की पहुंच बनी रहनी अत्यंत आवश्यक है। अन्यथा अर्थव्यवस्था का नुकसान तो होगा ही, आर्थिक असमानता और बढ़ेगी।

**प्रश्न:**- आप खुद को अगले कुछ सालों में किस रूप में देखना चाहते हैं?

**उत्तर:**- जैसा जनता चाहेगी। ❑❑

प्रमोद दीक्षित मलय

# भेदभावों से मुक्ति का उजास भरा पथ है मानवाधिकार

1975 में एक क़ानून बनाकर बंधुआ मज़दूरी को संज्ञेय दंडनीय अपराध घोषित कर देने से हज़ारों मनुष्यों को इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिली। विश्व में बाल मज़दूरी को भी इसी पंक्ति में रखा जा सकता हैं पर आज भी कम साक्षरता वाले राज्यों में अक्सर मानवाधिकार हनन की घटनाएं यथा पुलिस प्रताड़ना, झूठे केस में फंसाने एवं निर्दयता से मारने आदि प्रकाश में आती रहती हैं। इतना ही नहीं संपूर्ण विश्व में नारी गौरव, अस्मिता एवं अस्तित्व को हाशिए पर रखा गया है। मनुष्य एक शिशु के रूप में जन्म लेता है और शिशु को जन्म लेते ही मानव के रूप में गरिमामय जीवन जीने का अधिकार प्राकृतिक रूप से प्राप्त हो जाता है।

प्रत्येक मानव के लिए स्वतंत्रता, समानता और सम्मान के अधिकार के साथ जीवन में आगे बढ़ने और समाज जीवन के किसी भी क्षेत्र में काम करने एवं आगे बढ़ने हेतु भयरहित निर्बाध खुला मार्ग उपलब्ध है। किसी भी मानव प्राणी के साथ नस्ल, लिंग, जाति, भाषा, धर्म विचार, जन्म, रंग, क्षेत्र एवं देश के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता।

संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 10 दिसंबर, 1948 को विश्व मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी कर मानवाधिकारों की रक्षा कर मानव मूल्यों एवं आदर्शों के संरक्षण पर बल दिया। वर्ष 1950 से संयुक्त राष्ट्र से सम्बद्ध देशों द्वारा मानवाधिकार दिवस को मनाने एवं प्रचार-प्रसार करने हेतु सतत् प्रयास सराहनीय है। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मना कर संपूर्ण विश्व में मानव अधिकारों के प्रति सजगता और जागरुकता का प्रचार-प्रसार करते हुए मानवता के विरुद्ध हो रहे जुल्म एवं अत्याचारों को रोकने और उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने, खड़े होने और संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया जाता है। भारत में मानवाधिकार बहुत विलंब से लागू हुए। 28 सितंबर 1993 को मानवाधिकार कानून बनाया गया जिसके आलोक में 12 अक्तूबर 1993 को सरकार ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कर नागरिकों के हितों एवं अधिकारों की सुरक्षा हेतु पहल की

मानवाधिकारों का वर्तमान वितान भले ही आकर्षक एवं चेतनायुक्त दिखाई पड़ रहा हो पर मानव इतिहास तो क्रूरता, कुभाव, कलुषता, हिंसा, रुदन और अत्याचार से भरा हुआ है।

**जो सभ्यताएं तलवार एवं छल प्रलोभन के बल पर बढ़ीं वहां दास प्रथा को बढ़ावा और प्रश्रय मिला। युद्धबंदी, सामूहिक अपहरण और संगठित दास बाजार के उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता तो अमेरिकी आज़ादी के संघर्ष का नारा ही था। भारत भी इस अमानवीय प्रथा से अलग नहीं रहा। बंधुआ मज़दूरों के रूप में मानव का एक बड़ा वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अमानवीयजीवन जीने को अभिशप्त रहा है।**

इतिहास के पन्ने मनुष्य के रक्त से भींगे हैं और उसके शोषण की गाथा से भरे हुए भी मानव जीवन की इस यात्रा में ऐसे हज़ारों चित्र अंकित हैं जहां मानवता शर्मसार होती दिखाई देती है, जहां मनुष्य द्वारा ही मनुष्य को एक जानवर की भांति उपयोग और उपभोग की वस्तु बना दिया गया हो, जहां वह वस्तु की भांति बेचा, और खरीदा गया हो, जहां उसकी सांसों के स्पंदन पर नियंत्रण उसके मालिक का रहा हो। समृद्ध वर्ग द्वारा निर्धन व्यक्तियों के प्रति यह बर्ताव युगों युगों से पूरी दुनिया में जारी रहा है। एशिया, अफ्रीका, अमेरिका एवं यूरोपीय देशों में अमानवीय दास प्रथा को उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है।

जो सभ्यताएं तलवार एवं छल प्रलोभन के बल पर बढ़ीं वहां दास प्रथा को बढ़ावा और प्रश्रय मिला। युद्धबंदी, सामूहिक अपहरण और संगठित दास बाजार के उदाहरण इतिहास के पृष्ठों में दर्ज हैं। मनुष्य की स्वतंत्रता तो अमेरिकी आज़ादी के संघर्ष का नारा ही था। भारत भी इस अमानवीय प्रथा से अलग नहीं रहा। बंधुआ मज़दूरों के रूप में मानव का एक बड़ा वर्ग पीढ़ी दर पीढ़ी अमानवीय एवं अपमानजनक जीवन जीने को अभिशप्त रहा है। पर 1975 में एक कानून बनाकर बंधुआ मज़दूरी को संज्ञेय दंडनीय अपराध घोषित कर देने से हज़ारों मनुष्यों को इस नारकीय जीवन से मुक्ति मिली। विश्व में बाल मज़दूरी को भी इसी पंक्ति में रखा जा सकता हैं पर आज भी कम साक्षरता वाले राज्यों में अक्सर मानवाधिकार हनन की घटनाएं यथा पुलिस प्रताड़ना, झूठे केस में फंसाने एवं निर्दयता से मारने आदि प्रकाश में आती रहती हैं। इतना ही नहीं संपूर्ण विश्व में नारी गौरव, अस्मिता एवं अस्तित्व को हाशिए पर रखा गया है।

आधुनिक युग में दृष्टिगत करें तो मनुष्य एवं कतिपय देशों की साम्राज्यवादी नीति ने लाखों निर्दोष मनुष्य के लहू से वसुधा को रक्तिम किया है। प्रथम विश्व युद्ध से ही ये प्रश्न वैश्विक विचार फलक पर उभरने लगे कि एक मानव के रूप में उसके क्या अधिकार हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में लाखों नागरिकों की हत्या से इन प्रश्नों की स्याही और गहरी हुई। भारत-पाकिस्तान के बंटवारे में धर्मांधता की आग में लाखों जीवन झुलस गए और नारी अस्मिता तार-तार

रोज़गार

# फोटोनिक्स में हैं रोज़गार की असीम संभावनाएं

हम में से ज़्यादातर लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर्स के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिनका इस्तेमाल टेलीफोन, ब्रॉडबैंड और यहां तक की टीवी केबलों में सिग्नलों के संप्रेषण के लिए किया जाता है। लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं, जिन्होंने फोटोनिक्स के क्षेत्र में कैरियर बनाने के बारे में सोचा होगा। फोटोनिक्स प्रकाशीय ऊर्जा की एक तकनीकी है, जिसमें विकास की काफी संभावनाएं हैं। इलेक्ट्रानिक्स के बाद फोटोनिक्स को 21वीं सदी की टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। हालांकि फोटोनिक्स का दौर 1960 के दशक से शुरू हुआ, लेकिन लेजर के आविष्कार के साथ इसने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और टेलीकॉम सेक्टर के विकास में इससे काफी मदद मिली।

### क्या है यह

एक विषय के रूप में फोटोनिक्स काफी टेक्नीकल है। ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रानिक्स के संयोजन से यह तकनीक विकसित हुई है। भौतिकी की यह उपशाखा प्रकाश के सूक्ष्तम कण फोटॉन के अध्ययन से संबंधित है। सरल शब्दों में कहें तो यह सूचनाएं पाने और प्रेषित करने के लिए प्रकाश के इस्तेमाल की तकनीक है। यह लाइट के इमिशन, डिटेक्शन, ट्रांसमिशन और माडॅयुलेशन से जुड़ी तकनीकी में विशेषज्ञता हासिल करने का विज्ञान है। फोटोनिक्स सिस्टम में इंफॉरमेशन सिग्नल प्रकाशीय तरंगों के रूप में भेजे जो हैं और ये सिग्नल ऑप्टिकल फाइबरों के ज़रिए प्रेषित होते हैं।

### संभावनाएं

हाल के सालों में विश्वव्यापी टेलीकम्यूनिकेशन, कम्प्यूटिंग, सिक्युरिटी समेत और भी कई कार्यप्रणालियों में फोटोनिक्स बुनियादी तकनीक बन गया है। फोटोनिक्स को व्यावहारिक रूप से लागू करने के बढ़ते चलन ने इसे शोध व वाणिज्यिक विकास का अहम हिस्सा बना दिया है। फोटोनिक्स तकनीकी का इस्तेमाल इमेजिंग, चिकित्सा व स्वास्थ्य सेवा, प्रतिरक्षा, ऑप्टिक्स व इलेक्ट्रानिक्स में होता है। एडवांस्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी, लेजर, माइक्रोस्कोपी और फाइबर ऑप्टिक इमेजिंग के ज़रिए शोध संबंधी समस्याओं को सुलझाने में यह तकनीक खूब काम आती है। बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, सर्जरी व लाइफ साइंस में भी इसका इस्तेमाल होता है।

### रोज़गार

विज्ञान और ख़ासकर फिजिक्स व इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी रखने वाले लोग फोटोनिक्स में अपना कैरियर बना सकते हैं। एक फोटोनिक्स स्पेशलिस्ट किसी फोटोनिक्स कंपनी में इंजीनियर, टेक्नीशियन या साइंटिस्ट के तौर पर काम कर सकता है या किसी यूनिवर्सिटी अथवा सरकारी कार्यालयों में प्रोफेशनल आफीसर के तौर पर रोज़गार पा सकता है। इस क्षेत्र के विशेषज्ञ साइंटिस्ट के तौर पर काम पा सकते हैं। इस विद्या के इंजीनियर उपकरण डिजाइन करते हैं फोटोनिक्स टेक्नीशियन इंजीनियरों को डिजाइनिंग व मैन्युफैक्चरिंग में मदद करते हैं।

### पात्रता

देश के कई संस्थान फोटोनिक्स कोर्स की शिक्षा देते हैं। ऐसे छात्र जिन्होंने भौतिकी, रसायन और गणित विषय के साथ बारहवीं की परीक्षा न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो फोटोनिक्स एंड ऑप्टोमेट्रिक्स के ग्रेजुएशन कोर्स में दाख़िला ले सकते हैं। भौतिकी व गणित, एप्लाइड फिजिक्स या इलेक्ट्रानिक्स के साथ बैचलर डिग्री हासिल करने वाले अभ्यर्थी फोटोनिक्स या ऑप्टोमेट्रिक्स की मास्टर डिग्री के लिए आवेदन कर सकते हैं। फोटोनिक्स में एमटेक, एमफिल और पीएचडी करने की चाह रखने वाले अभ्यर्थियों के पास फिजिक्स अथवा फोटोनिक्स में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स भी है, जिनके लिए आवेदन किया जा सकता है। डिप्लोमा कोर्स कर आप फोटोनिक्स टेक्नीशियन बन सकते हैं। द्विवर्षीय टेक्नीशियन प्रोग्राम के जरिए भी फोटोनिक्स टेक्नीशियन बना जा सकता है।

### पारिश्रमिक

इस क्षेत्र से जुड़ा कोई शख़्स अपने कैरियर की शुरूआत में 20,000 से 30,000 रूपए मासिक तक की कमाई कर सकता है। विदेशों में इस क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों के लिए बेहतर संभावनाएं नज़र आ रही हैं। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में फोटोनिक्स रिसर्चर/साइंटिस्ट का पैकेज लाखों में हो सकता है।

### प्रमुख कंपनियाँ

भारत में इस क्षेत्र में काम करने वाली कुछ प्रमुख कंपनियों में ईगल फोटोनिक्स (बेंगलूर व चेन्नई), क्वालिटी फोटोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, स्फेयर ऑप्टिक्स, जे2 आप्ट्रोनिक्स, सहजानंद टेक्नोलाजीस प्राइवेट लिमिटेड, ऑप्टिवेव फोटोनिक्स लिमिटेड (हैदराबाद), जॉन एफ वेल्श टेक्नोलॉजी सेंटर (बेंगलुरु) और स्टरलाइट ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी लिमिटेड शामिल हैं।

### शिक्षण संस्थान

इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मुम्बई, नई दिल्ली।

मनिपाल अकादमी ऑफ हायर एजेकुशन। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ फोटोनिक्स, कोचीन। राजर्षि शाहू महाविद्यालय, डिपार्टमेंट ऑफ फोटोनिक्स, लातूर।

# इस्लामी दुनिया

## बीजिंग ओलंपिक के बहिष्कार से घटा उइगरों का उत्पीड़न

बीजिंग में हो रहे शीतकालीन ओलंपिक खेलों से पहले अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और आस्ट्रेलिया समेत कई देशों ने इनका राजनयिक बहिष्कार किया है। ये देश शिनजियांग में उइगर मुस्लिमों के साथ हो रहे अत्याचारों का विरोध करते हुए चीन पर लगातार दबाव बना रहे हैं। इस बीच विशेषज्ञों का दावा है कि पश्चिमी देशों के दबाव के बाद उइगरों मुस्लिमों पर उत्पीड़न कुछ घटा है।

## सीरियाई ने गिराई इस्राईल की मिसाइल

दमिश्क : सीरिया की हवाई रक्षा प्रणाली ने राजधानी दमिश्क के पश्चिमी एक क्षेत्र को निशाना बनाकर चलाई गई इस्राईल की कुछ मिसाइलों को गिराने में सफलता हासिल की। सीरियाई सरकारी समाचार एजेंसी सना के सैन्य स्रोतों का हवाला देते हुए बताया कि इस्राईल की ओर से छोड़ी गई यह मिसाइलें पूर्वी लेबनान की ओर से आई और दमिश्क के नज़दीक क्षेत्रों की चौकियों को निशाना बनाया। इससे सीरिया में काफी नुकसान भी हुआ है, दमिश्क में यह हमला तड़के करीब तीन बजे किया गया। इस्राईल सीरिया पर ज़्यादातर रात में ही हमले करता रहा है।

## इस्राईली राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान यूएई ने नष्ट की हूतियों की मिसाईलें

दुबई : यूएई के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि देश में इस्राईल के राष्ट्रपति आइजक हर्जोग की ऐतिहासिक यात्रा के बीच यमन के हूती आतंकवादी समूह ने एक और बैलेस्टिक मिसाइल दाग़ी जिसे बीच में ही नष्ट कर दिया गया है। हूतियों की बैलेस्टिक मिसाइल को नष्ट करने की इस माह यह तीसरी घटना है। इसका मलबा एक निर्जन क्षेत्र में गिरा, जहां कोई हताहत नहीं हुआ।

## कर चोरी मामले से पाकिस्तानी मीडिया कारोबारी बरी

लाहौर : पाक की एक अदालत ने देश के सबसे बड़े अख़बार जंग और जियो टीवी समूह के मालिक व प्रधानमंत्री संपादक मीर शकीलुर रहमान को अचल संपत्ति खरीद में कर चोरी के 35 वर्ष पूराने एक मामले से बरी कर दिया। रहमान को 2020 में गिरफ्तार किया गया था। अफसरों ने उन पर तीन दशक पहले नियमों का उल्लंघन कर सरकारी ज़मीन खरीदने का आरोप लगाया था। हालांकि रहमान ने इन आरोपों से इंकार किया था। उन्हें पिछले साल एक अन्य पाकिस्तानी अदालत ने ज़मानत दी थी।

# तालाब बचाने के लिए जुनून की ज़रूरत

**अतुल कनक**

जब लोगों को उनकी ज़रूरत का जल नलों के ज़रिए घरों में मुहैया नहीं होता था, तब कुएं, बावड़ी, टांकें, कुण्ड, तालाब, जोहड़ या झील लोगों की ज़रूरत पूरी किया करते थे। आकार और शैली के दृष्टि से इन जलस्रोतों की संरचना अलग-अलग होती थी, लेकिन सबके निर्माण का उद्देश्य वर्षा जल संग्रहण था। इससे न केवल धरती के अंतस को पानी भंडारण का मौक़ा मिलता था, बल्कि जिन दिनों बरसात नहीं होती थी, उन दिनों भी लोगों को जीवन की ज़रूरतें पूरी करने के लिए पानी आसानी से मिल जाया करता था। सार्वजनिक उपयोग के लिए जलस्रोत बनवाना पुण्यदायक माना जाता था।

अत्रि स्मृति, वामन पुराण, स्कंद पुराण जैसे ग्रंथों में तालाबों को पाटने या उनके पानी को गंदा करने वालों को पाप का भागी बताया गया है, लेकिन आज़ादी के बाद जब शहरों का विकास हुआ, नई बस्तियां और बाज़ारों की ज़रूरत हुई तो विकास के नाम पर अधिकांश तालाबों को या तो पाट दिया गया या फिर उन्हें उपेक्षा के साथ दुर्दशा के हवाले कर दिया गया। इस उपेक्षा का एक बड़ा कारण यह भी था कि जिस जल की ज़रूरत इन प्राचीन जलस्रोतों से जीवन का रिश्ता बनाए रखती थी, वह जल तो पाइपलाइन के ज़रिए आदमी के आंगन तक पहुंच गया। कई बार किसी व्यक्ति या वस्तु का सहजता से उपलब्ध हो जाना भी उसकी उपेक्षा का कारण बनता है। पानी के साथ यही हुआ है।

चूँकि नलों के माध्यम से घरों में जलापूर्ति के बाद अपनी आवश्यकता के जल संग्रहण के लिए प्राचीन जलस्रोतों तक नियमित जाने की सामान्य अनिवार्यता ख़त्म हो गई तो तालाबों, कुओं, बावड़ियों और कुण्डों की ही नहीं, नदियों तक की उपेक्षा के दिन शुरू हो गए। नदियों का पानी प्रदूषित होने लगा, बावड़ियों और कुंडों में गंदगी जमा होने लगी और तालाबों को काट या पाट कर नए निर्माण होने लगे। देश के अनेक शहरों में प्राचीन तालाबों की ज़मीन पर नई कालोनियां खड़ी कर दी गई है।

इस संबंध में राजस्थान के कोटा नगर का उदाहरण उल्लेखनीय है। भौगोलिक दृष्टि से कोटा उस हाड़ौती के पठार के सबसे निचले हिस्से पर बसा हुआ है, जो कभी ऐतिहासिक गोंडवाना पठार का हिस्सा हुआ करता था। जब कभी पठार के ऊपरी हिस्से में बारिश होती थी, पठार पर इकट्ठा हुआ पानी तेज़ी से नीचे की ओर दौड़ता था। सन 1326 में तत्कालीन बूंदी रियासत के राजकुमार धीरदेह ने इस पठार पर तेरह तालाब बनवाए, ताकि पठार के पानी को संग्रहित किया जा सके। सालभर ये तालाब न केवल लोगों को सिंचाई और घरेलू जरूरतों का पानी उपलब्ध कराते थे, बल्कि भूजल का स्तर बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। मगर समय के साथ ये तालाब कथित विकास की भेंट चढ़ गए। रंगतालाब, अनंतपुरा तालाब, काला तालाब आज भले बस्तियों के नाम हैं, लेकिन कभी इन बस्तियों के स्थान पर यहां भरे पूरे तालाब हुआ करते थे। छोटा तालाब में एक बाज़ार बना दिया गया, जो डकनिया तालाब को पाट कर उस पर एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन बना दिया गया। अब हालत यह है कि चंबल नदी के किनारे बसे इस शहर के कई इलाकों में भूजल का स्तर ख़तरनाक तरीके से नीचे चला गया है।

हालांकि यह पीड़ा केवल कोटा की नहीं है देश के अनेक हिस्सों में तालाबों की दुर्दशा से जनजीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना शुरू हो गया है। कुछ समय पहले जब बुंदेलखंड को आकाल का सामना करना पड़ा, तो उसकी भयावहता के लिए उस भूभाग के तालाबों की दुर्दशा को भी ज़िम्मेदार माना गया था। 2017 में उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पिछले चार दशक में बुंदेलखंड में चार हज़ार से अधिक तालाब ख़त्म हो गए। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में भी तालाब बहुत थे। मान्यता है कि पछिमाहा देव नामक शासक ने वहां सात सौ से अधिक तालाब खुदवाए थे। राजा बालंद के बारे में कहा जाता है कि वह आदमी से कर के रूप में लोहा वसूलता था और फिर तालाब खुदवाता था। हमारे सामाजिक जीवन की कई परंपराएं तालाबों से जुड़ी है। 1947 में भारत में तालाबों की संख्या चौबीस लाख थी।

कुछ तालाबों के निर्माण की कथा तो बहुत रोचक है। भोपाल का तालाब, जिसे भोज तालाब भी कहते हैं, संभवत: देश का सबसे बड़ा तालाब है। कहते हैं कि एक बार धार जिले के परमार शासक को कोई रोग हुआ। बहुत इलाज लिए लेकिन फायदा नहीं हुआ। किसी संत ने कहा कि अगर राजा 365 जलस्रोतों के जल से एक साथ स्नान करेंगे तो ही ठीक होंगे। परिणामस्वरूप इस तालाब का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश के ही सागर में स्थित लाखा बंजारे के तालाब के बारे में जनश्रुति है कि राजा ने तालाब तो खुदवा दिया, लेकिन उसमें जल की एक बूंद नहीं निकली। किसी ने कहा कि अगर कोई नवदंपति तालाब की जमीन में झूला झूलें तो जमीन से जल निकलेगा, लेकिन झूला झूलने वाले उसमें डूब जाएंगे। कोई इस बलिदान के लिए तैयार नहीं हुआ। तब लाखा नामक बंजारे ने जनहित के लिए अपने पुत्र और बहू से कहा कि वे तालाब की ज़मीन पर झूला झूलें। राजस्था के बूंदी ज़िले के हिंडौली कस्बे में स्थित एक तालाब ने अपनी सासू से कहा कि सासू मां गंदे पैर लेकर घर में क्यों आ गई, तो सासू ने ताना मारा कि कौन-सा तेरे पिता ने यहां हमारे लिए पैर धोने के पानी का इंतज़ाम कर रखा है? यह बात बहू के पिता को पता चली तो उसने गांव में एक तालाब ही बनवा दिया। मध्य प्रदेश में नरवर के ऐतिहासिक क़िले में एक तालाब है। नल दमयंती के महल के निकट स्थित इस तालाब के अंदर आठ कुएं और नौ बावड़ियां हैं। इस तालाब का निर्माण इसलिए कराया गया था ताकि युद्धकाल में परिस्थितियां कितनी ही विकट क्यों न हो जाएं, क़िले के अंदर रहने वालों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े।

**भोपाल का तालाब, जिसे भोज तालाब भी कहते हैं, संभवत: देश का सबसे बड़ा तालाब है। कहते हैं कि एक बार धार जिले के परमार शासक को कोई रोग हुआ। बहुत इलाज लिए लेकिन फायदा नहीं हुआ। किसी संत ने कहा कि अगर राजा 365 जलस्रोतों के जल से एक साथ स्नान करेंगे तो ही ठीक होंगे। परिणामस्वरूप इस तालाब का निर्माण हुआ। मध्य प्रदेश के ही सागर में स्थित लाखा बंजारे के तालाब के बारे में जनश्रुति है कि राजा ने तालाब तो खुदवा दिया, लेकिन उसमें जल की एक बूंद नहीं निकली। किसी ने कहा कि अगर कोई नवदंपति तालाब की जमीन में झूला झूलें तो जमीन से जल निकलेगा, लेकिन झूला झूलने वाले उसमें डूब जाएंगे। कोई इस बलिदान के लिए तैयार नहीं हुआ। तब लाखा नामक बंजारे ने जनहित के लिए अपने पुत्र और बहू से कहा कि वे तालाब की ज़मीन पर झूला झूलें। राजस्था के बूंदी ज़िले के हिंडौली कस्बे में स्थित एक तालाब ने अपनी सासू से कहा कि सासू मां गंदे पैर लेकर घर में क्यों आ गई, तो सासू ने ताना मारा कि कौन-सा तेरे पिता ने यहां हमारे लिए पैर धोने के पानी का इंतज़ाम कर रखा है? यह बात बहू के पिता को पता चली तो उसने गांव में एक तालाब ही बनवा दिया।**

तालाबों के साथ दंतकथाएं, परंपराएं और अनेक संस्कार कर्म जुड़े हैं, लेकिन कथित विकास ने अधिकांश तालाबों का गला घोंट दिया हैं ऐसे में कर्नाटक के मांड्या जिले के दासनदोड्डी गांव के बयासी वर्षीय चरवाहे कामेगोडा ने जो कर दिखाया, वह कइयों के लिए प्रेरक हो सकता है। कामेगोडा ने अपने प्रयासों और पैसों से अपने गांव के पास स्थित कुडिनीबेट्टा पहाड़ी पर चौदह तालाब बनवा दिए। करीब चार दशक पहले जब कामेगोड़ा इस पहाड़ी पर अपनी भेड़ें चराने जाता तो पशुओं और पक्षियों को पानी के लिए परेशान होते देखा। वे केवल उस पानी पर निर्भर थे, जो बरसात में गिरने के बाद इधर उधर किसी खड्डे में रह जाता था। कामेगोड़ा ने इस पानी को संग्रहित करने के लिए तालाब बनाने का निश्चय किया। अपनी कुछ भेड़ें बेच कर औज़ार खरीदें और फिर अकेले ही पहाड़ी पर तालाब खोदना शुरू कर दिया। इससे न केवल पशु पक्षियों को पानी मिलने लगा, बल्कि पहाड़ी पर हरियाली भी लौटने लगी। बाद में तो जैसे कामेगोड़ा को तालाब खोदने का नशा ही हो गया। इस काम के लिए विभिन्न संस्थाओं द्वारा मिले सम्मान की राशि उसने इसी काम पर ख़र्च कर दी। शुरू में जो गांव वाले उसे पागल कहते थे, जब वे उसका बहुत सम्मान करते हैं। तालाबों को बचाने के लिए समाज में ऐसे ही तो जुनून की ज़रूरत है।

# जलवायु परिवर्तन तथा अर्थव्यवस्था को लेकर हमें जल्द पछताना पड़ेगा

आकार पटेल

कुछ बदलाव हम तक इतने धीरे से पहुंचते हैं कि वर्तमान पीढ़ी उनके परिणामों की ज़िम्मेदारी नहीं लेती। स्वाभाविक तौर पर जलवायु परिवर्तन एक ऐसा मुद्दा है जिसे हम इस परिप्रेक्ष्य में ले सकते हैं। हमें याद है कि 1980 के दशक में 'ग्रीन हाउस गैस', 'क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स' तथा 'ओजन परत में छेद' जैसे शब्द सुनते थे। इनका इस्तेमाल स्कूल में भी किया जाता है अर्थात् लगभग 35 वर्ष पूर्व भी इस मुद्दे के बारे में सबको पता था। फिर भी इस बारे बहुत काम किया गया है और यही रवैया जारी है।

इसका एक कारण 2 लॉबियां हैं जो चाहती हैं कि कार्बन उत्सर्जन जारी रहे। तेल तथा गैस उद्योग विश्व का सबसे बड़ा व्यवसाय है तथा ऑटोमोबाईल निर्माता विश्व के दूसरे सबसे बड़े व्यवसाय है और निश्चित तौर पर ये दोनों कार्बनडाइ आक्साइड उत्सर्जन के प्रमुख स्रोत है, जो हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है।

दूसरा कारण यह है कि एक दौड़ के तौर पर हमने इस ख़बरे को गंभीरतापूर्वक नहीं लिया है क्योंकि हम महसूस करते हैं कि यह सीधे तौर पर हमारी पीढ़ी के लिए चिंता का विषय नहीं है। ज़रा सी अधिक गर्मी तथा जरा अधिक ठंडा मौसम हमें अपने जीवन के तरीके में नाटकीय बदलाव लाने तथा चीज़ों के लिए अधिक दाम चुकाने व अपने लिए असुविधा पैदा करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1985 से लेकर अब तक बड़े पैमाने पर वैचारिक प्रक्रिया ने कैसे काम किया तथा यही एकमात्र कारण है कि क्यों हमने जलवायु परिवर्तन को एक घटना के तौर पर स्वीकार किया लेकिन इसके बारे में बहुत अधिक करने में हिचकिचा रहे हैं। समस्या यह है, तथा एक बार फिर विशेषज्ञ हमारे कानों में चिल्ला रहे हैं कि यदि हमने इन चीज़ों पर काम नहीं किया तो अगले कुछ सालों में हमारे ग्रह को बहुत ख़राब स्थितियों से गुज़रना पड़ेगा। मगर हम निश्चितता के साथ कह सकते हैं कि हमने इस ख़बरे के ख़िलाफ़ निर्णायक तौर पर कार्य नहीं किया है।

एक अन्य क्षेत्र हमारी अर्थ व्यवस्था है, जहां ऐसा ही हो रहा है। मैंने पहले भी लिखा है कि हमारे सरकारी आंकड़े हमें बताते हैं कि हम किस ओर जा रहे हैं। आज लोग जितने काम लोग काम कर रहे हैं 2014 में इनसे 5 करोड़ अधिक भारतीय काम कर रहे थे (और यह मामला महामारी से पहले भी था)। 80 करोड़ लोग (जनसंख्या का 60 प्रतिशत) प्रतिमाह 6 किलो मुफ्त अनाज पर निर्भर है।

2 सालों तथा महामारी से 3 माह पहले से जी.डी.पी. की विकास दर में गिरावट आई है। इस वर्ष हमारी अर्थव्यवस्था उसी आकार की रहेगी, जैसी यह 2019 में थी लेकिन 2019 में यह पहले ही कमज़ोर थी। बांग्लादेश, जो 2014 में प्रति व्यक्ति जी.डी.पी. के मामले में हमसे लगभग 50 प्रतिशत पीछे था हम हमसे आगे है।

इसका कारण क्या है तथा हम किस ओर चल पड़े हैं? हम इन प्रश्नों का उत्तर तभी दे सकते हैं यदि हम पहले यह स्वीकार करें कि जिस तरह से अर्थ व्यवस्था का प्रबंधन किया जा रहा है उसमतें कुछ न कुछ ग़लत है। एक प्रक्रिया में तभी सुधार किया जा सकता है यदि हम स्वीकार कर लें कि हम एक ग़लत दिशा में जा रहे थे। चूंकि हम यह सोचते हैं कि हम सही है, हम वहीं पहुंचेंगे जहां हमें रास्ता ले जाएगा।

एक तीसरा क्षेत्र, जिसके परिणामों के बारे में हम पूरी तरह से नहीं समझे तथा उस परिपक्व तरीके से चर्चा नहीं कर रहे, वह समाज का सम्प्रदायीकरण, जो पूर्ण रूप है। आज अल्पसंख्यकों पर हमले, चाहे वे मुसलमान हों अथवा इसाई, इतने सामान्य हो गए हैं कि वे समाचार पत्रों को पहले पृष्ठों पर भी जगह नहीं बनाते योग्य समझे जाते। प्रतिदिन कुछ न कुछ नया होता है जो आमतौर पर सरकार अथवा सत्तासीन पार्टी द्वारा शुरू किया जाता है। अल्पसंख्यक भारतीयों का अनुमान यह है कि हिंसा ने हमारे समाज में काफी तेज़ी से स्थान बना लिया है। जलवायु परिवर्तन की तरह और संभवत: अर्थव्यवस्था के विपरीत इसे एक जबरन थोपे गए आचरण के तौर पर देखा जा सकता है। यह कहना ग़लत नहीं होगा कि सरकार जानबूझ कर जी.डी.पी. की वृद्धि को नाकाम कर रही है। मगर यह कहना सटीक होगा कि आज भारत को जानबूझ कर एक ऐसे चरण की ओर ले जाया जा रहा है जब साम्प्रदायिकता पूरी तरह से इसे संक्रमित कर देगी।

हमारे लिए इसके क्या परिणाम हैं? निम्न बातों पर ग़ौर किया जा सकता है। एक कमजोर अर्थव्यवस्था के कारण कुल विश्वास के स्तर नीचे हैं जिसका अर्थ यह हुआ कि निवेश कम रहेंगे। इस पर क़ानून को तोड़ने तथा भीड़ों को सशक्त करने तथा समूहों को हिंसक बनाने का और भी असर पड़ेगा। भारत जैसे बड़े आकार का देश एक बाहरी विश्व से घुसपैठ को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकता जो इसके भोजन के हिस्से को खाना शुरू कर दे। यह पहले ही हो चुका है तथा भारत उन देशों की सूचि में शामिल है जिनके ख़िलाफ़ 2019 से प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव किया गया है (हालांकि इसे सक्रिय नहीं किया गया)।

युवाओं की एक पीढ़ी और संभवत: दो पीढ़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिनका आंतरिक दुश्मनों को लेकर सोच बारे 'ब्रेन वॉश' किया जा रहा है। फिर संस्थाओं को नुकसान पहुंचाया जा रहा है जिन्हें दशकों के दौरान नाज़ुकता से खड़ा किया गया। इनमें न्यायपालिका तथा चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक इकाईयां शामिल हैं जो 2014 के बाद से कार्यपालिका के निर्देशों पर काम कर रही है। इनके अतिरिक्त सिविल सर्विसेज तथा सशस्त्र बलों जैसी संस्थाएं हैं जो सरकार तथा सत्ताधारी पार्टी की सोच के मुताबिक इतिहास में पहले से कहीं अधिक काम कर रही है।

हमने यह अपने साथ खुशी मनाते हुए किया है और इसलिए इस पर रुकना और वापस मुड़ना आसान नहीं होगा। अंग्रेज़ी की एक कहावत है कि 'जल्दबाज़ी में काम करना और फुर्सत में पछताना।' जलवायु परिवर्तन तथा अर्थव्यवस्था के मामले में हमें जल्दी ही पछताने का अवसर मिलेगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि हम ऐसा फुर्सत में करने में सक्षम होंगे।❑❑

## बजट से गांव-गरीब किसान को नहीं बल्कि कारपोरेट मित्रों को होगा लाभ: भारतीय किसान यूनियन

केंद्रीय वित्त निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट पेश किया और सरकार ने कृषि क्षेत्र से जुड़े कई अहम ऐलान किए हैं। हालांकि किसान संगठन नाखुश नज़र आ रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन ने कहा कि, बजट खेती के लिए नकारात्मक है। बजट में केवल अमृत महोत्सव, गतिशक्ति, ई विद्या जैसे शव्दों का मायाजाल है। कृषि में पूंजी निवेश के माहौल के लिए कोई योजना नहीं है और देश की वित्त मंत्री को बजट के लिए शून्य नंबर देते हैं। दरअसल बजट में सरकार ने कृषि सेक्टर में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का ऐलान किया है। वहीं वित्त मंत्री ने धन और गेहूं की खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने का फैसला किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि, किसानों के लिए बजट रूटीन प्रकिया का हिस्सा है। इससे किसानों का कल्याण संभव नहीं है। वहीं सरकार किसानों से बदले की भावना से कार्य कर रही है। तिलहन के उत्पादन को आप इसलिए बढ़ाना चाहते हैं कि ताड़ की खेती आप कारपोरेट को सौंपना चाहते हैं। यह खेती भूमिगत जल व पर्यायवणीय दृष्टि उचित नहीं है।

## ख़ास ख़बरें

### अगर अमेरिका ने ताइवान का समर्थन किया तो जंग : चीन

यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे तनाव में मौक़ा देख रहे चीन ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर उसने तालवान की आज़ादी का समर्थन किया तो दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य संघर्ष हो सकता है। दक्षिण चीन सागर में तनावपूर्ण माहौल के बीच अमेरिका में चीन के राजदूत किन गांग ने कहा कि ताइवान चीन व अमेरिका के बीच सबसे विस्फोटक मुद्दा है। गांग ने कहा कि ताइवान के अधिकारी अगर लगातार आजादी की राह पर बढ़ते है तो जंग को कोई नहीं रोक सकेगा। इस धमकी पर पेंटागन ने कहा कि वह अभी भी 'एक चीन' की नीति और अमेरिका ताइवान संबंध कानून पर क़ायम है।

### यूजर ट्रेकिंग : हर्जाने के ख़िलाफ़ गूगल की अपील ख़ारिज

फ्रांस : फ्रांस के एक कोर्ट ने यूजर प्राइवेसी का उल्लंघन कर ऑनलाइन निगरानी के मामले में 840 करोड़ रुपए (11.20 करोड़ डॉलर) के जुर्माने के ख़िलाफ़ गुगल की अपील ख़ारिज कर दी है। प्राइवेसी मामलों पर नज़र रखने वाली संस्था ने 2020 में यह जुर्माना लगाया था। इसके ख़िलाफ़ उसने अपील की थी। गूगल पर अक्सर विज्ञापन के मकसद से डेटा इकट्ठा करने वाले ट्रैकिंग डिवाइस के यूजर को ट्रैक करने के लिए आलोचना का सामना करना पड़ता है। नियामक संस्था का कहना सही था कि गूगल ने यूजर की पूर्व सहमति हासिल नही की।

### अगर मशीनें सुपर इंटेलीजेंस हो गईं तो इंसान का अस्तित्व ख़तरे में

लंदन : दुनिया के जानी मानी जाने वाली हस्तियों में शुमार स्टुअर्ट रसेल ने प्रतिक्रिया दी थी कि इंटेलिजेंस मशीनों को हम अपनी भलाई के हिसाब से डिजाइन नहीं करते तो हमारा अस्तित्व खतरें में पड़ जाएगा। रसेल बताते हैं कि फिलहाल सबसे बड़ी समस्या घातक हथियारों की है। वे पहले से ही हमारे बीच में हैं। रसेल का कहना है कि टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग से इंसानों का अस्तित्व ही ख़तरे में आा सकता है।

### योगी फिर सीएम बने तो पलायन करूंगा : मुनव्वर

लखनऊ: यूपी चुनाव में पाकिस्तान पलायन और जिन्ना जैसे शब्द चर्चा में हैं। इस बीच शायर मुनव्वर राणा ने एक इंटरव्यू में कहा, 'वर्तमान सरकार पलायन- पलायन रट रही है, लेकिन भाजपा सरकार में मुसलमानों में इतना खौफ है कि कोई बोल नहीं सकता हैं अगर भाजपा की सरकार जा जाती हे तो मैं यहां से पलायन कर लूंगा।' राम मंदिर पर फैसला आने के बाद उन्होंने पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर सवाल उठा दिया था। किसान आंदोलन के दौरान उन्होंने कहा था कि संसद भवन को गिराकर वहां खेत बना देना चाहिए।

# नशाखोरी
## एक ख़तरनाक बीमारी

**मौलाना असरारुल हक़ क़ासमी**

अल्लाह तआला ने इंसान को बेहतरीन सांचे में ढाला है। सही रास्ते की तरफ इनकी रहनुमाई की है और हिदायत बख़्शी है। अच्छा रिज़्क़ दिया, बहुत सारी नेमतों से नवाज़ा इताअत व फरमाबरदारी और इबादत के लिये अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने की तरग़ीब थी, जैसाकि इरशाद है ''जो कुछ अल्लाह ने तुमको हलाल और पाक रिज़्क़ दिया इसे खाओ और अललाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, अगर तुम सिर्फ इसी की इबादत करने वाले हो।''(अलनहल 114)

लिहाज़ा एक मुसलमान का वतीरा से होना चाहिये कि वह हर चीज़ की पहले जांच करे, फिर इसको इस्तेमाल करे, चाहे वे खाने की चीज़ हो, पीने की हो पहनने की चीज़ हो या ज़िंदगी गुज़ारने का कोई ख़ास तरीक़ा हो, हमारे नबी सल्ल॰ का अंदाज़ यही था, जैसा कि अल्लाह ने आपके बारे में फरमाया है ''वह नबी इन मुसलमानों के लिये पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं और नापाक (या नुकसानदेही) चीज़ों को हराम करते हैं। (अल एराफ : 157)

अहले इल्म की तशरीह के मुताबिक़ तैय्यब हर वह चीज़ है जिसे अल्लाह ने हलाल किया है ऐसी चीज़ पाक है और जिस्मानी और शरअी तौर पर फायदा पहुंचाने वाली है और चीज़ को अल्लाह ने हराम क़रार दिया है, वह बुरी और नुकसानदेह है, अल्लाह तआला का इरशाद है ''ऐ लोगों! ज़मीन से निकलने वाली हलाल और पाक चीज़ें खाओ और शैतान के नक़्शे क़दम पर मत चलो, बेशक वह तुम्हारा खुला दुश्मन है।

(अल बक़रा : 168)

इस आयत में अल्लाह तआला ने इंसान को ज़मीन से निकलने वाली पाकीज़ा और हलाल चीज़ों के खाने का हुक्म दिया है, यानि ऐसी चीज़ें जो फिन नफस भी अच्छी हो और इंसान जिस्मो अक़्ल के लिये भी नुकसानदेह न हो और इस सिलसिले में शैतान के पदचिह्नों पर चलने से मना किया है।

दरअसल शैतान हमेशा इस ताक में रहता है कि वह इंसान को राहे ख़ुदा से भटका दे, इसे हलाल माकूलात व मशरुबात से दूर करके नशाआवर वस्तुओं के इस्तेमाल में मुब्तला कर दे और इसकी अक़्ल जिसके द्वारा अल्लाह ने इंसान को सबसे मुमताज़ किया है, पर पर्दा डाल दे, इसी वजह से हमारी शरीअत ने हर उस चीज़ को हराम क़रार दिया है, जिससे इंसान की अक़्ल को नुकसान पहुंचे, चुनांचे हज़रत उम्मे सलमा से मरवी है वह फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी सल्ल॰ ने हर नशाआवर और अक़्ल में फतूर पैदा करने वाली चीज़ के प्रयोग से रोका है (अबू दाऊद)। इस अवसर पर आपने नशीली वस्तुओं की हुरमत को ताक़ीदी तौर पर बयान करते हुये फरमाया, ''जिस चीज़ की ज़्यादा मिक़दार नशाआवर हो इसकी कम मात्रा भी हराम है।''(अबू दाऊद)

मेरे भाईयों! अक़्ल की नेमत इंसानों पर अल्लाह का एक अज़ीम अहसान है, इसी के ज़रिये वह ख़ैर व शर के बीच फर्क करे, इससे देश और राष्ट्र का निर्माण होता है। इसी के इस्तेमाल से इंसान अपने रब की इबादत और इसकी मुनाज़ात करता और लोगों के बीच अच्छी ज़िन्दगी

**अल्लाह के रसूल सल्ल॰ ने फरमाया है कि ''अल्लाह तआला ने ये तय कर रखा है कि जो शख़्स नशेवाली चीज़ को इस्तेमाल करेगा, इसको तैय्यतुल खबाल, पिलाया जायेगा सहाबा ने पूछा, ये क्या है, तो आप सल्ल॰ ने फरमाया दोज़ख़ियों के बदन से निचड़ा हुआ पसीना (मुस्लिम), जिस आदमी की अक़्ल ख़त्म हो जाये, इसकी हिकमत व बसीरत भी जाती रहती है।**

गुज़ारता है। हज़रत उमर बिन खताब फरमाते हैं कि ''इंसान की हक़ीक़त इसकी अक़्ल से पता चलती है, इसका हस्ब नस्ब इसके धर्म से और इसकी शराफ़त मरवत इसके अख़लाक़ से पता चलती है। यही वजह है कि जो आदी नशीली वस्तुओं का प्रयोग करे, वह अपनी जान और अक़्ल को नुकसान पहुंचाता है, इसे अल्लाह ने दोज़ख़ियों का पसीना पिलाने की धमकी दी।

अल्लाह के रसूल सल्ल॰ ने फरमाया है कि ''अल्लाह तआला ने ये तय कर रखा है कि जो शख़्स नशेवाली चीज़ को इस्तेमाल करेगा, इसको ''तैय्यतुल खबाल, पिलाया जायेगा सहाबा ने पूछा, ये क्या है, तो आप सल्ल॰ ने फरमाया दोज़ख़ियों के बदन से निचड़ा हुआ पसीना (मुस्लिम), जिस आदमी की अक़्ल ख़त्म हो जाये, इसकी हिकमत व बसीरत भी जाती रहती है, ऐसा आदमी जिस्मानी तौर से भी कमज़ोर होता है और जानबूझ कर अपने आपको बर्बाद करता है।

हमें याद रखना चाहिये कि हमारी जानें अल्लाह की अमानत है, किसी को भी इनमें अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ तसर्रुफ करने की इजाज़त नहीं, अल्लाह का फरमान है कि ''आप कह दीजिये कि मेरी नमाज़ मेरी कुर्बानी, मेरी ज़िन्दगी और मेरी मौत, अल्लाह के लिये है। (अलइनाम : 162) इसी वजह से अल्लाह ने इंसान को अपने ऊपर या किसी दूसरे पर जुल्म ज़्यादाती करने से रोका है, फरमाता है कि अपने आप को हलाक मत करो, बेशक अल्लाह तुम पर रहम करने वाला है और शख़्स ऐसा करता है जुल्म ज़्यादती करने वाला तो है इसको जल्दी ही जहन्नुम में डालेंगे। (अलनिसा : 29-30)। यानि अगर कोई शख़्स मना करने के बावजूद हद से गुज़रते हुये, जुल्म करते हुये इसकी हुरमत को जानते हुये अल्लाह की नाफरमानी की जुर्रत करके ऐसा का करे तो हम इसे जहन्नुम रसीद करेंगे, अल्लाह के रसूल सल्ल॰ फरमाते हैं, कि जिस आदमी ने ज़हर खाकर खुद को मार डाला तो क़यामत के दिन वह ज़हर इसके हाथ में होगा और वह जहन्नुम में इसे खाता रहेगा।

नशीली चीज़ों की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि जो आदमी ऐसी चीज़ों का आदि हो जाता है, वह अल्लाह की तरफ से अता करदा नेमत माल को बर्बाद करता रहता है, जबकि हमारे नबी सल्ल॰ का फरमान है कि ''अल्लाह तआला को तीन बातें नापसंद है, बेजां बातचीत, माल को बर्बाद करना और बहुत ज़्यादा सवाल करना। (मुत्तफिक अलैह) इसी तरह जिनको नशे की लत लग जाये, वह अपने सम्बन्धियों के प्रति आयद होने वाली ज़िम्मेदारियों को अदा करने में कोताही बरतते है, इनका परिवार बिखर जाता है और ये बहुत बड़ा गुनाह है, अल्लाह के रसूल सल्ल॰ फरमाते हैं, कि ''इंसान के गुनाहगार होने के लिये ये काफी है कि वह अपने घरवालों को बर्बाद कर दे। (अबू दाऊद) यानि इनके हुकूक़ अदा न करे, एक मौक़े पर आपने फरमाया ''अल्लाह तआला हर निगरां और ज़िम्मेदार से इस चीज़ के बारे में पूछेगा जिसका इसे निगरां बनाया गया था कि इसने इसकी हिफाज़त की या बर्बाद कर दिया, यहां तक कि इंसान से इसके घरवालों के सम्बन्ध से भी पूछताछ होगी। (निसाई) गर्ज़ इस तरह की बुरी और हलाकत चीज़ों से बचने

# नूरे क़ुरआन

## (सूरा अल क़द्र नं॰ 97)

**अनुवाद और व्याख्या : शैख़ुल हिन्द र.अ.**

अर्थात् बहुत मज़बूत बंटी हुई चुभने वाली कुछ व्याख्याकारों के अनुसार इससे दोज़ख़ के तौक (हंसली) और जंज़ीर मुराद हैं और यह उपमा जो सर पर ईंधन लिए फिरती है, के सम्बन्ध से दी गई है क्योंकि लकड़ियों का बोझ उठाने में रस्सी की ज़रूरत पड़ती है। लिखते हैं कि इस औरत के गले में एक बहुमूल्य हार था। कहा करती थी कि लात और उज्जा (काबे के दो बड़े बुत जिनका वर्णन सूरा नं॰ 53 रुकू नं॰ 1 में आ चुका है। जिनकी इस्लाम से पहले पूजा करते थे) की क़सम इसको मुहम्मद सल्ल॰ की मुख़ालफ़त में ख़र्च कर डालूंगी। आवश्यक था कि दोज़ख़ भी उसकी गर्दन हार से ख़ाली न रहे और विचित्र बात यह है कि इस अभागन की मौत इसी प्रकार हुई। लकड़ियों के गद्टड़ की रस्सी गले में आ पड़ी, जिससे गला घुटकर दम निकल गया।

***( सूरा इख़लास नं॰ 112 )***

यह सूरा मक्का में उतरी इसमें चार आयते हैं।

*प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।*

***आप की दीजिए कि वह अल्लाह एक है।***

अर्थात् जो लोग अल्लाह के सम्बन्ध में पूछते हैं कि वह कैसा है उनसे कह दीजिये कि वह एक है, जिसके अस्तित्व में किसी प्रकार की संख्या और दुई नहीं कोई उसके मुकाबिल और उसके समान नहीं। इससे मजूसियों के विश्वास का खण्डन हो गया जो कहते हैं कि अल्लाह दो हैं। अच्छी वस्तुओं का पैदा करने वाला यजदां और बुरी चीज़ों का पैदा करने वाला अहरमन है और मूर्ति पूजकों का भी खंडन हो गया, जो तैंतीस करोड़ देवताओं को अल्लाह के साझीदार बनाते हैं।

***अल्लाह बे-नियाज़ ( वह किसी का मोहताज नहीं, उसके सब मोहताज हैं ) है।***

समद शब्द की व्याख्या कई प्रकार से की गई है। तिबरानी (एक बड़े व्याख्याकार) उन सबको नक़ल करके कहते हैं। यह सब अर्थ ठीक है और यह सब हमारे रब के गुण हैं। उसी की ओर तमाम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आकर्षित होते हैं अर्थात् सब उसके मोहताज हैं, वह किसी का मोहताज नहीं है और वही है जिसकी बड़ाई कमाल और अच्छाईयों में असीमित है। उससे बड़ा कोई नहीं और वही है जो खाने-पीने की इच्छा से पाक है और वही है जो समस्त सृष्टि के नष्ट हो जाने के पश्चात् भी बाक़ी रहने वाला है। अल्लाह के इस गुण से उन मूर्खों का खंडन हुआ जो अल्लाह के अतिरिक्त किसी को किसी रूप में पूर्ण अधिकार रखने वाला समझते हैं और कार्यों के पदार्थवाद और आत्मा का भी खंडन हो गया क्योंकि उनके नियमानुसार अल्लाह तो संसार के बनाने में इन दोनों का मोहताज है परंतु ये दोनों अपने अस्तित्व में अल्लाह के मोहताज नहीं।

***उसके सन्तान नहीं और न वह किसी की संतान है।***

अर्थात् न कोई उसकी सन्तान न वह किसी की औलाद। इसमें उन लोगों का खंडन हुआ जो हज़रत मसीह या हज़रत उज़ैर को अल्लाह का बेटा और फरिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहते हैं दूसरे जो लोग मसीह या किसी व्यक्ति को अल्लाह मानते हैं उनका खण्डन भी कर दिया गया है अर्थात् अल्लाह की शान यह है कि उसको किसी ने न जना हो और सब जानते हैं कि हज़रत मसीह एक सच्चरित्र औरत के पेट से पैदा हुये, फिर वह किस प्रकार अल्लाह हो सकते हैं।

रुकू नं॰ 1

***और न कोई उसके जोड़ का है।***

जब उसके जोड़ का कोई नहीं तो पत्नी या बेटा कहां से हो सकता है, इस वाक्य में उन क़ौमों का खण्डन किया गया है जो अल्लाह के किसी सृष्टि को उसके बराबर मानते हैं। कुछ उद्दण्ड लोग तो उससे बढ़कर गुण दूसरों में सिद्ध करते हैं। यहूद की किबातें उठाकर देखो, एक दंगल में अल्लाह की कुश्ती याकूब अ. से हो रही है और याकूब अल्लाह को पछाड़ देते हैं।

## ( सूरा अल फलक़ नं॰ 113 )

यह सूरा मदीने में उतरी इसमें पांच आयतें हैं।

प्रारंभ करता हूं मैं अल्लाह के नाम से जो असीम कृपालु महादयालु है।

***आप की दीजिए कि मैं प्रातःकाल के रब की शरण लेता हूं।***

अर्थात् जो रात के अंधेरे को फाड़कर प्रातःकाल की रोशनी उत्पन्न करता है।

***उसकी बनाई हुई हर वस्तु की बुराई से।***

अर्थात् हर ऐसी उत्पन्न की हुई वस्तु से जिसमें किसी प्रकार की बुराई हो उसकी बुराई से पनाह मांगता हूं। उसके पश्चात् कुछ विशेष वस्तुओं का वर्णन किया।

# उ०प्र० : भाजपा ने अपना दल को दी स्वार टांडा सीट

गुड़ खाएं, गुलगुले से परहेज़। यह मुहावरा राजनीतिक दलों पर एकदम सटीक बैठता है। रामपुर जिले की स्वार टांडा सीट पर भाजपा ने इसी मुहावरे को चरितार्थ किया है। समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला आज़म खान के मुकाबले भाजपा इस सीट पर किसी मुस्लिम उम्मीदवार को ही उतारना चाहती थी पर एक तो उसे खुद मुसलमानों से परहेज़ है, दूसरे इलाके में कोई कद्दावर मुसलमान नेता नहीं जो भाजपा के चुनाव चिह्न पर लड़ने की हिम्मत दिखा पाए। इसलिए पार्टी ने अपनी सहयोगी अनुप्रिया पटेल के अपना दल को यह सीट थमा दी। यह बात अलग है कि रामपुर में अपना दल का न कोई संगठन है और न ही जनाधार।

रामपुर क्षेत्र में दो दशक पहले तक पूर्व रामपुर रियासत के नवाब रहे मिक्की मियां का दबदबा था। लोकसभा चुनाव पहले मिक्की मियां जीतते थे उसके बाद उनकी पत्नी बेगम नूर बानो संसद पहुंचती रहीं। लेकिन शहर की विधानसभा सीट पर जलवा मोहम्मद आज़म खान का ही बना रहा। पिछले विधान सभा चुनाव में रामपुर शहर से आज़म खान ही जीते थे लेकिन पार्टी ने 2019 में उन्हें लोकसभा चुनाव भी लड़ा दिया। वे लोकसभा जीत गए और विधानसभा से इस्तीफा दे दिया।

आज़म ख़ान के इस्तीफे के बाद रामपुर शहर सीट के उपचुनाव में उनकी पत्नी जीत गई। उधर स्वार टांडा सीट से चुने गए। आज़म ख़ान के बेटे अब्दुल्ला की विधान सभा सदस्यता उनकी जन्मतिथि में हेराफेरी के आधार पर अदालत ने रद्द कर दी। हालांकि इस सीट पर अदालती रोक के कारण ही उपचुनाव नहीं हो पाया। अब आम चुनाव है तो फिर अब्दुल्ला आज़म उम्मीदवार हैं। रामपुर में तो भाजपा ने आज़म ख़ान के मुक़ाबले आकाश सक्सेना को उतार दिया पर स्वार टांडा में अब भाजपा सहयोगी अपना दल के कंधे पर बंदूक रख अब्दुल्ला से चुनावी जंग करेगी।

समाजवादी पार्टी ने भी गठबंधन करते हुए एक नया प्रयोग किया है। राष्ट्रीय लोकदल की ज़्यादा सीटों की मांग तो अखिलेश यादव ने ज़रूर मान ली पर पश्चिम की छह सीटों पर उन्हें उम्मीदवार भी अपने थमा दिए। मतलब यह है कि सपा के उम्मीदवार इन सीटों पर साइकिल के बजाय रालोद के चुनाव चिह्न हैंडपंप से लड़ेंगे। इस सीट पर रालोद की दावेदारी ज़्यादा थी। हालांकि 2012 में यहां सपा के गुलाम मोहम्मद विजयी हुए थे और 2017 में भाजपा के जितेन्द्र सतवाई। गुलाम मोहम्मद तब दूसरे नंबर पर रहे थे। यानि रालोद इस सीट पर जीतना तो दूर पिछले दो चुनावों में दूसरा स्थान भी हासिल नहीं कर पाया था। यहां सबसे ज़्यादा मतदाता मुसलमान ही हैं। उसके बाद जाट और दलित मतदाता हैं। रालोद इस सीट से अपना जाट उम्मीदवार उतारने के मूड में था। पर आख़िर में जयंत चौधरी को ज़मीनी हक़ीक़त का अहसास करना पड़ा। अखिलेश ने भी दरियादिली दिखाते हुए सीट अपने उम्मीदवार सहित रालोद को सौंप दी ताकि जाट और मुसलमान गठबंधन कारगर साबित हों।

भारतीय जनता पार्टी के मनिंदर पाल सिंह इस असंतोष को हवा देकर जाट मतदाताओं का 2017 की तरह भाजपा के पक्ष में ध्रुवीकरण करने की जुगत में थे। पर असंतोष दो दिन के भीतर ही थम गया। अब स्थिति ऐसी है कि भाजपा उम्मीदवार किसानों के विरोध के कारण गांवों में दाख़िल होने से भी डर रहे हैं। इस विधानसभा क्षेत्र के छूर गांव में तो भाजपा उम्मीदवार के घुसने का ही किसानों ने विरोध किया। उम्मीदवार के वापस न जाने पर उनके काफ़िले पर हमला भी बोल दिया। कैराना में हिन्दुओं के पलायन के मुद्दे को 2017 की तरह ही उभारने की मंशा से अमित शाह के चुनाव प्रचार की शुरुआत के चौबीस घंटे बाद ही कई सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों के विरोध से संकेत मिलता है कि भाजपा के प्रति किसानों खासकर जाट मतदाताओं की नाराज़गी दूर नहीं हुई है। ❑❑

# पंजाब : सियासत में नौकरशाहों का बढ़ा दबदबा

बाहुबल की जगह बुद्धिबल को तरजीह देने के कारण ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में विद्रोह की आवाज़ें उठने लगी थीं। उस समय प्रदेश में अफरशाही इस क़दर हावी थी कि मंत्री और आला अफसर की आपसी झड़प में आला अफसर को हटाने के बजाय मंत्री का महकमा बदल दिया गया था। अफसरशाही के दबदबे के कारण ही इस बार कांग्रेस, भाजपा और उसके गठबंधन के साथी और आम आदमी पार्टी सभी खुले दिल से अफसरों की राजनीति के पक्ष में दिखाई दे रहे हैं। तभी तो टिकट देने में भी इस वर्ग के लिए हाथ खुला रखा गया है।

प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब तक जारी सूचि के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने लुधियाणा जिले के दो आला अधिकारियों को उतारा है। जिले के गिल विधानसभा हलके से निवर्तमान आइएएस एसआर लद्दड़ को टिकट मिला है। वे सेवा में रहते हुए भी कई संगठनों के साथ जुड़कर काम करते रहे हैं। लद्दड़ खेती कानूनों के ख़िलाफ़ किसानों के लिए संघर्ष के कारण चर्चा में रहे। किसान आंदोलन के समर्थक लद्दड़ ने किरती किसान यूनियन शेर-ए-पंजाब पार्टी बनाई जिसका उन्होंने भाजपा में विलय कर दिया। भाजपा ने लुधियाणा जिले के ही जगरांव विधानसभा सीट से पूर्व तहसीलदार कंवर नरिंदरपाल को उतारा है। जगराओ आरक्षित सीट है। यहां से अकाली दल ने एसआर कलेर को टिकट दिया है। कलेर लुधियाणा में एडीसी रहे हैं। इस सीट पर दो पूर्व आला अधिकारी मैदान में हैं जिनका मुक़ाबला आप विधायक सर्वजात कौर माणुके से होगा।

पंजाब में किडनी कांड, फर्जी टेलिफोन एक्सचेंज जैसे मामलों को उजागर करने और बेअदबी कांड की जांच करने वाले आईपीएस कुंवर विजय प्रताप सिंह ने नौकरी से इस्तीफा दिया और आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया। आप ने उन्हें अमृतसर नार्थ से उम्मीदवार बनाया है। संयुक्त समाज मोर्चा ने पूर्व आइएएस खुशीराम को टिकट दिया है। खुशीराम ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में बसपा टिकट पर भाग्य आज़माया था। अब उन्हें चब्बेवाल से टिकट दिया गया है।

मलेरकोटला से भी कांग्रेस उम्मीदवार रज़िया सुल्ताना का प्रचार उनके पति पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा संभाले हुए हैं। रज़िया सुल्ताना निवर्तमान विधायक हैं और कहा जाता है कि उनकी सारी सियासी ज़िम्मेदारी उनके पति ही संभालते हैं। हाल ही मोहम्मद मुस्तफा की वायरल हुई विवादित वीडियो ने उनके लिए कुछ मुश्किलें भी खड़ी कर दी है। इससे पहले वर्ष 2019 में हुए लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने आइएएस अमर सिंह को फतेहगढ़ साहिब से उम्मीदवार बनाया और वे जीत गए। अमर सिंह ने केन्द्र व मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में बतौर आईएएस बेहतर काम किया और अब वे राजनीतिक पारी भी सफलता के साथ खेल रहे हैं।

पंजाब में अमरिंदर सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए फगवाड़ा

बाक़ी पेज 11 पर

# उत्तराखंड : कोरोना की पाबंदियों के बीच बिगड़े मौसम ने चुनाव प्रचार को किया प्रभावित

उत्तराखंड में कोरोना महामारी के साथ भारी बर्फबारी और कड़ाके की ठंड ने जनवरी माह के आख़िर में चुनाव प्रचार की रफ्तार बिल्कुल धीमी कर दी है। कोरोना विषाणु के बढ़ते संक्रमण के मद्देनज़र चुनाव आयोग ने हालांकि 31 जनवरी तक राजनीतिक रैलियों पर पाबंदी लगा रखी थी और बर्फबारी ने चुनाव प्रचार अभियान की रफ्तार थाम दी।

अधिकतम 10 लोगों के साथ घर-घर जाकर मतदाताओं से संपर्क और बड़े हाल में 50 प्रतिशत की क्षमता के साथ बैठकों तक सिमट समिट गए, चुनाव प्रचार अभियान में मौसम का बिगड़ा मिजाज प्रत्याशियों के लिए दुश्वारियां पैदा कर रहा है। भारी हिमपात के कारण प्रदेश के बहुत से गांव सीधे संपर्क से कट गए हैं, जहां पहुंच पाना उम्मीदवारों के लिए 'दुरुह' साबित हो रहा है।

बद्रीनाथ से मौजूदा विधायक और भाजपा प्रत्याशी महेन्द्र भट्ट ने कहा कि बारिश और हिमपात के कारण पिछले कई दिन से वह छाता लेकर और गमबूट पहनकर गांव-गांव में लोगों से संपर्क किया। मौसम की वजह से कई क्षेत्रों में आने जाने में अधिक समय लगा। इस संबंध में जोशीमठ ब्लाक के दुरमी गांव का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि वहां पहुंचने में सामान्यत: एक घंटा लगता है, लेकिन खराब मौसम के चलते उन्हें वहां पहुंचने में दो घंटे से भी ज़्यादा का समय लगा और लोगों से संवाद में दिक्कतें आई।

उत्तराखंड में 70 में से करीब दो दर्जन विधानसभा सीटें ऐसी हैं, जिनके अनेक क्षेत्र सर्दियों में बर्फ की चपेट में रहते हैं। इनमें प्रमुख रूप से केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मसूरी, धारचूला, चकराता, पुरोला, नैनीताल और धनोल्टी शामिल है। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र का 35-40 प्रतिशत हिस्सा बर्फबारी से प्रभावित रहता है और इस बार तो। यहां रिकॉर्ड बर्फबारी हुई हैं यहां दोबारा विधानसभा में पहुंचने का प्रयास कर रहे कांग्रेसी प्रत्याशी और विधायक मनोज रावत ने माना कि इस बार हमेशा के मुकाबले मौसम ज़्यादा खराब है और प्रचार में दुश्वारियां पैदा हो रही हैं। बर्फ से ढंके मचकंडी, अकोडी और बडच ग्रामसभाओं तक पहुंचने में सामान्य के मुक़ाबले दोगुना समय लगा। रावत स्वंय बडच गांव के निवासी हैं।

धामी सरकार में कैबिनेट मंत्री और डीडीहाट से भाजपा प्रत्याशी बिशन सिंह चुफाल ने बताया कि बर्फबारी के बीच उन्होंने मनपापो और मनडा ग्रामसभाओं में अपने लिए वोट मांगे। हालांकि, चुफाल ने कहा कि बर्फबारी अड़चन तो है, लेकिन मतदाताओं तक पहुंचने में वह हर बाधा को पार करेंगे। ❑❑

# जैसे कप्तानी ली थी वैसे ही छोड़ी कोहली ने

विराट कोहली ने सात साल पहले जिस तरह से टैस्ट कप्तानी की ज़िम्मेदारी संभाली थी, कुछ उसी अंदाज़ में उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। 2014-15 के आस्ट्रेलियाई दौरे के बीच ही महेन्द्र सिंह धोनी ने जब अचानक टेस्ट कप्तानी छोड़ दी तो विराट कोहली को टीम इंडिया की कमान सौंपी गई थी। इस बार दक्षिण अफ्रीकी दौरे पर रवाना होने से पहले कोहली वनडे कप्तानी से हटाए जाने के ढंग से आहत थे।

दौरे से पहले किए गए संवाददाता सम्मेलन में उनके खुलासे से बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली की विश्वसनीयता पर भी सवालिया निशान लग गया था। इन सबके बावजूद दक्षिण अफ्रीका टेस्ट सीरीज जीतने असफल रहने पर भी किसी ने विराट से टेस्ट कप्तानी से इस्तीफा देने की अपेक्षा नहीं की थी।

विराट कोहली को हमेशा दिल से फैसला लेने वाले व्यक्ति के तौर पर जाना गया है। टेस्ट कप्तानी छोड़ना भी दिल से लिया गया फैसला ही लगता है। वह वनडे कप्तानी लेने के ढंग से तो निराश थे ही, रवि शास्त्री के कोच पद छोड़ने से उन्होंने ड्रेसिंग रूम में एक मज़बूत समर्थक भी खो दिया था। पिछले सात सालों में वह कप्तान के तौर पर जिस तरह से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैसले करते रहे थे, वह स्थिति आगे रहने की संभावना कम थी और उनके इस्तीफे के पीछे के तथ्य की भूमिका भी हो सकती है। उन्होंने जिस तरह सोशल मीडिया पर वक्तव्य जारी करके इस्तीफा दिया, उससे भी यह समझा जा सकता है कि उनके बीसीसीआई से संबंध कैसे चल रहे थे। कहा जा रहा है कि केप्टाउन के न्यूलैंड्स में तीसरा टैस्ट और सीरीज़ हारने के बाद ही उन्होंने ड्रेसिंग रूम में टीम के साथियों को अपने इस फैसले की जानकारी दे दी थी और उनसे इस बात को ड्रेसिंग रूम से बाहर न जाने देने का आग्रह किया था।

विराट कोहली को वनडे कप्तानी से हटाने के साथ ही रोहित शर्मा को वनडे का कप्तान और टेस्ट टीम का उपकप्तान बनाए जाने से यह साफ हो गया था, अब बीसीसीआई के लिए विराट के मुकाबले रोहित ज़्यादा अहम हो गए हैं। संभवत: इसे समझते हुए ही विराट ने समय रहते टेस्ट कप्तानी छोड़ने का फैसला किया।

कोहली को टीम इंडिया का हुलिया बदल देने वाले कप्तान के तौर पर याद किया जाएगा। वह खुद तो पूरी तरह फिट रहते ही हैं, अपने इस विश्वास को समूची टीम की सोच का हिस्सा बनाकर अपने टीम के फिटनेस कल्चर को हल बदल दिया। वह टीम में चार पेस गेंदबाज़ों का इस्तेमाल करने वाले पहले भारतीय बनें। उन्होंने टीम के पेस अटैक को किसी भी परिस्थिति में 20 विकेट लेने वाला बनाया। इसी का परिणाम था कि भारत पहली बार आस्ट्रेलिया टैस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा। यही नहीं इंग्लैंड के पिछले दौरे पर पांचवें टेस्ट के कोरोना के प्रकोप की वजह से स्थगित होने तक भारतीय टीम ने 2-1 की बढ़त बना ली थी। इसमें कोई दो राय नहीं कि विराट की सात सालों की कड़ी मेहनत का ही परिणाम है कि अब भारतीय टीम कैसे भी हालात में जीतने की सोच रखती है।

सही मायनों में विराट ने टीम के सोच को नई आक्रामकता प्रदान की। इसी का परिणाम है कि हमारे युवा पेस गेंदबाज़ भी अब विदेश में खेलने के दौरान गेंदबाज़ी करते समय बल्लेबाज़ी को खा जाने वाली निगाह से घूरने का माद्दा रखते हैं।

विराट ने जब 2014-15 में टीम की कमान संभाली थी, तब भारत टैस्ट रैंकिंग में सातवें स्थान पर था। वह टीम को पहली रैंकिंग पर ले ही नहीं गए, उसे पहली पायदान पार पांच सालों तक बनाए रखा भी। पर विराट कोहली को पहली विवश टैस्ट चैम्पियनशिप में भारत को फाइनल तक पहुंचाकर चैम्पियन नहीं बना पाने का दर्द हमेशा सालता रहेगा। यही नहीं उन्हें तीनों प्रारूपों में टीम इंडिया का कप्तान रहते हुए कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं दिला पाने का भी मलाल रहेगा।

जिस कप्तान ने टीम की सोच को ऐसी धार दी, उसे आक्रामकता प्रदान की, वह यदि बदलाव के दौर से गुज़रने वाली दक्षिण अफ्रीकी टीम के ख़िलाफ़ सीरीज नहीं जीत पाता है तो उसका मायूस होना स्वाभाविक ही है। विराट ने माना भी कि बल्लेबाज़ों के नहीं चल पाने की वजह से भारत यह सीरीज हारा है।

विराट के कप्तानी से हटने के फैसले के बाद बहुत संभव है कि श्रीलंका के साथ होने वाली घरेलू सीरीज में कोई बदलाव देखने को मिले। इसमें अंजिक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा की छुट्टी भी संभव है। वैसे भी टीम इंडिया के कोच के रूप में राहुल द्रविड़ आ ही चुके हैं और टेस्ट कप्तान के तौर पर रोहित के आने की पूरी संभावना है। इस स्थिति में टीम में बदलाव हो ही

बाक़ी पेज 11 पर



# आपकी मुश्किलें न बढ़ा दे 'मौसमी एलर्जी'

आज हम कोरोना महामारी के दौर में है, लगभग दो वर्ष से हम इस महामारी को मात देने में लगे हैं। इसके लक्षण यूं तो हम सब को तकरीबन पता ही है, पर इसके बावजूद कुछ दूसरी समस्याओं से भी हमें समग रहने की आवश्यकता है। मौसमी एलर्जी को यूँ तो बदलते मौसम की समस्या माना जाता है, लेकिन इस मौसम में भी इसका असर बना रहता है। इसमें छींके आना, नाक बंद होना या बहना बहुत मामूली बात है। इसके अलावा गले में ख़राश रहती है। साथ ही साथ आंखों में खुजलाहट या लाली महसूस होती है। इसमें खांसी भी काफी बढ़ जाती है। शोध के मुताबिक सर्दी के मौसम में आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और इस मौसम की आम समस्या सर्दी जुकाम आपको आसानी से अपनी गिरफ्त में ले सकते हैं।

### क्या हैं कारण

हालांकि धूल मिट्टी, फफूंद आदि तो हर वक्त हमारे वातावरण में मौजूद रहते हैं लेकिन ठण्ड के मौसम में ये हमें इसलिए तेज़ी से पकड़ते हैं, क्योंकि हम अपने कमरे के खिड़की दरवाज़े बन्द कर लेते हैं। इसके अलावा ठण्ड से बचाव के लिए हीटर की मदद भी लेने लगते हैं। ऐसे में कमरे का वातावरण इन चीज़ों को तेज़ी से पनपने में उनकी मदद करता है।

### एलर्जी को जानना ज़रूरी

एलर्जी दो तरह की होती है। पहली मौसमी, जो बदलते मौसम के कारण होती है और दूसरी बारहमासी जो सालभर चलती है। आइए जानते हैं वो कौन से ऐसे दुश्मन हैं, जो वातावरण में मौजूद रहते हैं और हमें मौसमी एलर्जी की क़ैद में पहुंचा देते हैं।

### धूल-मिट्टी के कण

आमतौर पर साफ दिखने वाले घरों में भी सैकड़ों डस्ट पार्टिकल्स यानि धूल मिट्टी के कण वातावरण में मौजूद रहते हैं। कभी सजावटी सामान के पीछे तो कभी गद्दे के नीचे। कभी पर्दे के अंदर तो कभी तकिए के ऊपर। इतना ही नहीं, पायदान पर साफ किए गए हर जूते में धूल के कण रह जाते हैं, मगर नज़र नहीं आते। यही धूल कण आंखों में खराश, छींकों, खांसी, नाक बंद और नाक बहने का सबब साबित होते हैं।

### फंगल इन्फेक्शन

नमी वाली जगह जैसे बाथरुम, बेसमेंट या गैराज में फंगल इन्फेक्शन आसानी से पनपता है। ऐसी जगहों में घुसते ही हमें अलग सी महक आती है और जब हम हम सांस लेते हैं तो वहां फैले फंगल इन्फेक्शन का हमारे शरीर पर हमला हो जाता है। इसके अलावा कई बार हमारे कमरे की दीवारें भी सीलन से भर जाती हैं, जिसके कारण घर में फंगल इन्फेक्शन, से एलर्जी का खतरा बना रहता है, जो बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीज़ों के लिए बेहद ख़तरनाक है।

### पालतू जानवरों से एलर्जी

घरों में पालतू जानवर हमेशा हमारे इर्द-गिर्द रहते हैं। उन्हें खाना खिलाना, घुमाने ले जाना और सुलाना हमारा ही काम होता है। ऐसे में वह बार-बार हमारे संपर्क में आते हैं। इस तरह उनके बाल, रूसी, लार और उनके जीवाणु हमारे कपड़ों, जूतों आदि से चिपक जाते हैं, जिससे हम आसानी से एलर्जी का शिकार हो जाते हैं।

### फूड एलर्जी

कई लोगों को खाने की चीज़ों से भी जल्दी एलर्जी हो जाती है, इसलिए बासी खाना न खाएं। इसके अलावा बाजार में मिलने वाले मसालेदार भोजन से भी परहेज़ करें।

### ख़ुशबू से एलर्जी

आमतौर पर लोगों को छींक मारते या जुकाम की चपेट में आते देखा जा सकता है। इसका एक मुख्य कारण खुशबू से होने वाली एलर्जी हैं इसलिए जो लोग परफ्यूम का अधिक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हल्की खुशबू वाले परफ्यूम का इस्तेमाल करना चाहिए या परफ्यूम का इस्तेमाल बन्द कर देना चाहिए। कई बार हमारे कपड़ों पर लगने वाला परफ्यूम हमारे बच्चों के लिए परेशानी का सबब साबित हो सकता है और वह रह-रह कर जुकाम की चपेट में आ सकते हैं।

### ज़रूरी बातें

सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है।

मौसमी एलर्जी बच्चों से लेकर किसी भी उम्र के लोगों को प्रभावित कर सकती है।

यदि खांसी या नाक बहने जैसी कोई भी समस्या एक सप्ताह से ज़्यादा बनी रहे तो तुरंत डाक्टर से सम्पर्क करें।

उपचार डॉक्टर की सलाह से ही करें।

घर में ताज़ी हवा आने का रास्ता रखें।

एलर्जी से बचाव के लिए सूरज की किरणों को घर के अंदर आने दें।

अदरक, लहसुन, शहद और तुलसी एलर्जी से बचाव के लिए ज़रूरी है।

### घरेलू नुस्खे

एलर्जीसे छुटकारा पाने के लिए नींबू के रस में शहद मिला कर एक गिलास गुनगुने पानी में डालें। इसे रोज़ाना पीने से आपका इम्यून सिस्टम मज़बूत होगा।

गर्म पानी की भाप लेने से भी आप एलर्जी से दूर रह सकते हैं।

नीम की पत्तियों का किसी भी रूप में सेवन करके आप एलर्जी को तत्काल दूर भगा सकते हैं। ❑❑

## शेष.... धधकते कजाकिस्तान....

हैं कि इन तमाम घटनाक्रमों को जोड़ें तो यूरेशिया की भू-राजनीति में एक नया जुड़ाव नज़र आता है जिसमें रूस की केन्द्रीय भूमिका है। कजाकिस्तान आज इतिहास के दोराहे पर खड़ा है। एक तरफ उसकी जनता में अपने वर्तमान शासकों की नीतियों को लेकर असंतोष जनांदोलन का रूप ले रहा है, साथ ही देश में बढ़ती अशांति से विदेशी निवेशकों के कजाकिस्तान में निवेश करने से कुछ हद तक पीछे हटने का अंदेशा भी नज़र आता है। ज़रूरी है कि राष्ट्रपति कासिम योमात तोकायेव पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान की शक्तिशाली छाया से निकल कर बिना बल प्रदर्शन के जनता के सरोकारों को लेकर सीधे उनसे बातचीत करें। हालांकि इन सबके बीच वहां के सबसे बड़े नेता और 29 वर्ष तक राष्ट्रपति रह चुके नूर सुल्तान नजरबायेव संभवत: अपने ख़िलाफ़ बढ़ते जनअसंतोष के चलते सार्वजनिक जीवन में नज़र नहीं आ रहे हैं। कजाकिस्तान का आगे का रास्ता वहां के शासकों, राष्ट्रपति कासिम को जनता से सीधे जुड़कर ही तय करना होगा।❑❑

## शेष.... भेदभावों से मुक्ति....

हुई। पूरे विश्व में महिलाओं के श्रम का शोषण था और कुछ देशों में मतदान के अधिकार से वंचित भी। इन तमाम संदर्भों के धरातल पर तब संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकारों पर न केवल चर्चा परिचर्चा करके एक रास्ता खोजने की पहल की गई बल्कि सर्वसम्मति से मानवाधिकारों का एक घोषणा पत्र भी जारी हुआ। इस वैश्विक घोषणा पत्र में प्रत्येक व्यक्ति को गरिमामय स्वतंत्र जीवन जीने की सुरक्षा का अधिकार मिला। मनुष्य की मनुष्य द्वारा की जा रही दासता से मुक्ति का उजास भरा पथ मिला। यातना, पीड़ा, क्रूरता से आज़ादी और एक मानव के रूप में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता का भी अधिकार प्राप्त हुआ। और यह भी किसी भी राज्य-सत्ता द्वारा किसी भी व्यक्ति की मनमाने ढंग से गिरफ्तारी करने, हिरासत में रखने और देश से निर्वासन पर अंकुश लगा ग़ैर कानूनी बना दिया। जब तक अदालत द्वारा आरोपी पर दोष सिद्ध न हो जाए तब तक उसे निर्दोष होने का अधिकार भी प्रदत्त है। घर, परिवार एवं पत्राचार में निजता की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोई भी व्यक्ति अपने देश के अंदर एवं अन्य किसी भी देश में भ्रमण करने, अपने देश की नागरिकता त्यागने एवं अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करने और किसी भी देश में राजनीतिक शरण पाने का (ग़ैर राजनीतिक अपराध को छोड़कर) अधिकार रखता है।❑❑

## शेष.... सियासत में नौकरशाहों....

उपचुनाव में तो आइएएस बलविंदर सिंह ने सुबह नौकरी से इस्तीफा दिया और शाम को कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार घोषित कर दिया। राजनीति उन्हें रास नहीं आई और बाद में वे सामान्य जीवन में लौट गए। आइएएस व आइपीएस के पंजाब की राजनीति में सक्रिय होने का यह पहला मामला नहीं है। इसकी शुरूआत 90 के दशक में आइपीएस सिमरनजीत सिंह मान ने की। जिन्होंने पंजाब में गरमपंथी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए अकाली दल अमृतसर का गठन किया और एक बार संसद की दहलीज़ तक भी पहुंचे। सिमरनजीत सिंह मान ने संसद में कृपाण लेकर जाने, बैलगाड़ी में जाने आदि को लेकर खूब सुर्खियां बटोरी। वर्तमान में सिमरनजीत मान एक विशेष विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके अलावा पंजाब में कई अधिकारी ऐसे भी हैं, जिन्होंने सक्रिय राजनीति में हिस्सेदारी निभाने की बजाय राजनीतिक नियुक्तियों को अहमियत दी है। आइपीएस मोहम्मद मुस्तफ़ा कांग्रेस प्रधान नवजोत सिद्धू के सलाहकार हैं। उनकी पत्नी पंजाब की अध्यक्ष हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार ने राजनीतिक नियुक्तियों में 13 पूर्व नौकरशाहों को स्थान दिया गया। अमरिंदर सरकार में राजनीतिक नियुक्तियां पाने वालों में तेजिन्दर कौर, डीपी रेड्डी, पूर्व पुलिस महानिदेशक एस.के. शर्मा मुख्य रूप से शामिल रहे हैं।❑❑

## शेष.... जैसे कप्तानी ली थी....

सकता है।

विराट कोहली को हेशा देश के सफलतम टेस्ट कप्तान के तौर पर याद किया जाएगा। उन्होंने 68 टेस्ट में भारत की कप्तानी करके 40 टैस्ट में भारत को जीत दिलाई। सफलता के मामले में देश में उनका कोई सानी नहीं है। वह दुनिया के चौथे सबसे सफल कप्तान हैं। उनस आगे सिर्फ ग्रेम स्मिथ (101 टेस्ट में 53 जीत), रिकी पोंटिंग (77 टेस्ट में 48 जीत), और स्टीव वॉ (57 टेस्ट में 41 जीत) ही आगे हैं।

इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि देश के सफलतम टेस्ट कप्तान को सीरीज हारकर और विवादास्पद माहौल में जाना पड़ा। अगर विराट और बीसीसीआई के बीच संबंध मध ुर होते तो उन्हें श्रीलंका के साथ होने वाली अगली घरेलू सीरीज तक कप्तानी छोड़ने से रोका जा सकता था। इस स्थिति में देश के सफलतम कप्तान की इस ज़िम्मेदारी से मुक्ति जीत के साथ हो सकती थी। लेकिन जब किसी कप्तान और बीसीसीआई अध्यक्ष के बीच विश्वास संकट पैदा हो जाए, तो फिर उस स्थिति को लंबा खींचने की वकालत नहीं की जा सकती। इसलिए मौजूदा हालात में नए कप्तान का आना टीम के लिए अच्छा ही है।❑❑

## शेष.... प्रथम पृष्ठ

प्रधानमंत्री जी के वह होंट जो साधारण सी बातों पर खुलकर बोलते हैं इस मामले में पूरी तरह बंद पड़े है जो ज़ाहिर है लोकतंत्र का खुला मज़ाक है। देश के कुछ बुद्धिजीवियों ने यह प्रश्न उठाया भी है कि इससे हमारे प्रधानमंत्री भारत और विश्व के मुसलमानों को आख़िर क्या संदेश देना चाहते हैं।

इण्डियन मुस्लिम फॉर सेकुलर एंड डेमोक्रेसी (आई.एम.एस.डी.) ने हरिद्वार में होने वाली 'धर्म संसद' में भारतीय मुसलमानों के नरसंहार की खुलेआम अपील करने के मामले में प्रधानमंत्री जी की चुप्पी को 'घिनौना नाटक' और भारतीय लोकतंत्र का 'खुला ठठा' बताते हुए उनसे पूछा कि वह भारत और विश्व के मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं।

आई.एम.एस.डी. ने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री जी की नरसंहार की खुली अपील पर भी चुप्पी साध ने वाले लोकतांत्रिक जगत के इकलौते नेता हैं। उसने आरोप लगाया कि खुलेआम नफ़रत फैलाने वाली धर्म संसद उसी 'हिन्दुत्व फैक्ट्री' का अटूट भाग है जिसे समय-समय पर स्वयं खुद ईंधन सप्लाई करते हैं। डॉन में 'ग्लोबल जेनोसाइड वॉच' के मुखिया डॉ. ग्रेगी इस्टेंटन के हवाले से कहा गया है कि भारत के नेता होने के नाते प्रधानमंत्री का फर्ज़ था कि वह उसकी निंदा करते लेकिन उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा, बयान में यह भी कहा गया कि 2020 में केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के 'गोली मारो, सालों को' के लेकर कार्रवाई न करने का भी ज़िक्र किया है।

बयान में कुछ माह पहले आर. एस.एस. के मुखिया मोहन भागवत की इस टिप्पणी का ज़िक्र किया गया है, सभी भारतीयों का डी.एन. ए. सामान्य है और मुसलमानों के बग़ैर हिन्दुत्व की कल्पना की जा सकती, अगर कोई हिन्दू कहता है कि भारत में मुसलमानों को नहीं रहना चाहिए तो वह हिन्दू नहीं है। मुसलमान नस्लकुशी की अपील को लेकर भागवत की चुप्पी का भी प्रश्न उठाया गया है। इसमें पूछा गया है कि मोदी और भागवत अपनी ख़ामोशी से देश और दुनिया के मुसलमानों को क्या पैग़ाम देना चाहते हैं।

इस सूरतेहाल का एक दुखदायक पहलू यह भी है कि प्रधानमंत्री जी इस क़ातिलाना सोच की निन्दा तो क्या करते उन्होंने 20 जनवरी 2022 को सफेद पोश भारतीय महिलाओं की एक संस्था 'ब्रह्मकुमारिज' के एक अधिवेशन में उन काल्पनिक धर्म संसदों में किए जाने वाले एलानात का विरोध करने वालों को ही यह कहकर कठघरे में खड़ा करने की कोशिश की "यह लोग देश की विदेशी छवि को दाग़दार करने की कोशिश कर रहे हैं" साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि देश में एक ऐसा निज़ाम बनाया जा रहा है जिस में पक्षपात की कोई जगह नहीं होगी। इसी अधिवेशन को राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलौत ने भी संबोधित किया था जिन्होंने प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा था कि "अमन और भाईचारा समय की अहम आवश्यकता है क्योंकि देश इस समय उग्रता का शिकार है" बहुत मुमकिन प्रधानमंत्री ने इसी संदर्भ में यह बात कही हो फिर उनके सामने तो देशभर के बुद्धिजीवियों, प्रोफेसरों, नौकरशाहों और सशस्त्र सेनाओं के उन रिटायर्ड उच्च अधिकारियों के बयानात और अपीलें भी होगी जो उन्होंने उन काल्पनिक धर्मगुरुओं के इश्तेआल अंगेज़ बयानात की निन्दा में जारी किए है और खुद प्रधानमंत्री से मुंह खोलने की अपील की है।

बहरहाल प्रधानमंत्री बोले और बोले भी वह जिसकी उनसे उम्मीद की जा सकती थी जिसे भारत जैसे आज़ाद लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष संविधान के हामिल देश के लोकतंत्र का खुला मज़ाक न कहा जाए तो आख़िर और क्या कहा जाए, जहां तक मुसलमानों और देश की दूसरी अल्पसंख्यकों का संबंध है वह देश के मौजूदा शासकों के नज़रियात और विचार से पूरी तरह अवगत है। उनका अपने पाक परवरदिगार पर पूरा भरोसा है और जब तक यह भरोसा क़ायम है विश्व की कोई शक्ति भी उनका बाल बीका नहीं कर सकती, फिरऔन आते हैं औ चले जाते हैं, ईमानवालो को आज तक कोई न मिटा सका है, न झुका सकी है, हमारे मौजूदा शासकों की भी यह बात अच्दी तरह समझ लेनी चाहिए।❑❑

## शेष.... मंज़र पस-मंज़र

सकारात्मक संकेत भी है कि पिछले कुछ दिन में संक्रमण दर कम पड़ रही है। 21 जनवरी को संक्रमण दर करीब 18 फीसद पर आ गई और लगातार नीचे आ रही है जो फिलहाल 4 फीसद पर है। कुल जमा हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं जिसमें हालात तेजी से ऊपर नीचे हो रहे हैं। इसलिए अभी यह कह पाना मुश्किल है कि तीसरी लहर का चरम आ चुका है या नहीं

हम अभी ख़तरनाक दौर से निकल नहीं पा रहे हैं। अब कोरोना के नए बहुरूप ओमिक्रॉन ने इन हालातों में बढ़ोत्तरी ही की है। ओमिक्रॉन का भी नया स्वरूप आने की ख़बरें हैं। ऐसे में सबसे बड़ा संकट इस बात का खड़ा हो गया है कि संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने वालों की जांच का कोई मतलब नहीं रह गया है। अब यह भी नहीं पता लग सकता कि कौन किसको संक्रमित कर रहा है। यही बेहद ख़तरनाक स्थिति है। यह संकट इसलिए भी बड़ा है कि ओमिक्रॉन विषाणु अब तक के सारे कोरोना रूपों में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक ज़िन्दा रहने वाला स्वरूप है। ज़ाहिर है, ख़तरे का स्तर भी पहले के मुक़ाबले कई गुना ज़्यादा है इसके फैलने की रफ्तार भी कई गुनी है। इसका जो नया रूप यानि बीए-2 मिला है, उसका तो जांच में भी पता नहीं चल पा रहा। यानि अब ऐसे हालात का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें विषाणु का सामुदायिक प्रसार होने की आशंका है, जांच का कोई फायदा नहीं हो रहा और ख़तरे का स्तर बढ़ता ही जा रहा है।

इसलिए बार-बार प्रश्न घूम फिर कर वहीं आ जा रहा है कि बचाव कैसे हो? अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो महामारी से पिंड नहीं छूटने वाला। एकाध सप्ताह में कभी मामले गिरने लगते हैं तो लगात है कि अब मुक्ति मिली। पर फिर अचानक बढ़ते संक्रमण और मौतों के मामले चिंता बढ़ा देते हैं। अकेले केरल में पचपन हजार से ज़्यादा मामले एक दिन में मिलना कोई कम गंभीर बात नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडू की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है। हालांकि टीकाकरण ने जोखिम के स्तर को कम किया है। पर बचाव के दो बड़े उपायों मास्क और सेनिटाइजर से हाथों की सफाई भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सेनिटाइजर से हाथों की सफाई किसी भी विषाणु की सफाई का उपाय बताया जा रहा है। फिलहाल बेहतर यही है कि हम सुरक्षा संबंधी सभी उपायों का पूरी तरह पालन करें, बचाव ही में सुरक्षा है।❑❑

## देश में कब आएगी 5जी मोबाइल सर्विस?

केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि वित्त वर्ष 2023 में 5जी स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि साल 2022 में 5जी के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी 2022 में 5ळ के स्पेक्ट्रम नीलाम होने से इसकी सलवस को वित्त वर्ष 2022-23 में जारी किया जाएगा। देश में 5जी मोबाइल की बिक्री जोरों पर है लेकिन नेटवर्क के नाम पर अब भी 4जी ही देश में है। ऐसे लोग जो 5जी मोबाइल रखे हुए हैं या खरीदना चाहते हैं वो बेसब्री से 5जी नेटवर्क का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी एक साल और इंतजार करना पड़ेगा। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसको लेकर 5जी की लॉचिंग के लिए स्कीम लाई जाएगी। बजट में ये भी कहा गया पीपीपी मॉडल के तहत गांवों और रिमोट एरिया में फाइबर ऑपटिक्स के जरिए इंटरनेट को पहुंचाया जाएगा ताकि सभी को बेहतर कनेक्टिविटी मिल सके।

**SHANTI MISSION** (HINDI WEEKLY) NEW DELHI Postal Registration No. DL(C)-01/1266/2021-23
Publishing Date : **30 Jan.2022** Posting Days : **MON. - TUE.** at **N.D.P.S.O.** New Delhi-110002 R.N.I. 57270/93



# •चुनाव का चक्र •सम्मान की गूँज

# •वायरस के नए स्वरूप : बढ़ता ख़तरा

## चुनाव का चक्र

प्रधानमंत्री ने एक बार फिर एक राष्ट्र एक चुनाव के सिद्धांत पर बल दिया है। पहले भी कई अवसरों पर वे कह चुके हैं कि देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने चाहिए। अलग-अलग चुनाव होने से धन और समय की बहुत बर्बादी होती है। प्रधानमंत्री के इस सिद्धांत का उपराष्ट्रपति ने भी समर्थन किया है। इस बात से शायद ही कोई इंकार करे कि बार-बार चुनाव होने से न सिर्फ पैसे की काफी बर्बादी होती है, बल्कि चुनाव प्रक्रिया के प्रति मतदाता में उदासीनता भी पैदा होती है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं मानी जाती। प्रधानमंत्री ने इस बिन्दु का विशेष रूप से उल्लेख किया कि बहुत सारे पढ़े लिखे शहरी मतदाता मतदान में उत्साह के साथ हिस्सा नहीं लेते। पिछले कुछ सालों से स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि हर साल कहीं न कहीं चुनाव होते हैं। इस तरह देश में हर समय चुनाव का माहौल बना रहता है। जिन राज्यों और केन्द्र में एक ही पार्टी की सरकारें हैं ये कहीं वह प्रतिपक्षी दल के रूप में है, वहां जब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो केन्द्र सरकार भी सक्रिय नज़र आती है। उसी के अनुसार कई बार फैसले भी करती देखी जाती हैं इसी तरह राज्य सरकारें भी लोकसभा चुनाव के समय अपने दल को ध्यान में रखकर कर सरकारी तंत्र का उपयोग करती हैं। यह अब जैसे स्वीकृत परंपरा का रूप ले चुका है

**आज़ादी के शुरुआती कुछ सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। इससे राजनीतिक दलों को भी फायदा होता था और सरकारी अमले और मतदाता को भी बार-बार चुनाव की गहमागहमी से निजात मिलती थी। मगर कुछ विधानसभाओं में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और कई बार लोकसभा के भी मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, जिसकी वजह से एक साथ चुनाव कराने का चक्र बिगड़ गया।**

लोकतंत्र में चुनाव की अवधि तय होती है। हमारे संविधान में चुनाव को लेकर बहुत स्पष्ट प्रावधान हैं। पांच वर्ष के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए, चाहे वह लोकसभा का हो या विधानसभा का। आज़ादी के शुरुआती कुछ सालों में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते थे। इससे राजनीतिक दलों को भी फायदा होता था और सरकारी अमले और मतदाता को भी बार-बार चुनाव की गहमागहमी से निजात मिलती थी। मगर कुछ विधानसभाओं में सरकारें अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई और कई बार लोकसभा के भी मध्यावधि चुनाव कराने पड़े, जिसकी वजह से एक साथ चुनाव कराने का चक्र बिगड़ गया। संवैधानिक बाध्यता है कि किसी भी सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद किन्हीं स्थितियों में अगर चुनाव सम्पन्न नहीं कराए जा पाते, तो राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ता है। उसकी अवधि भी छह माह होती है। इसे लंबे समय तक नहीं बढ़ाया जा सकता। इसलिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ कराने में बाधा आती है। अब चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल जिस तरह के हथकंडे अपनाने लगे हैं, धनबल और बाहुबल का इस्तेमाल करने लगे हैं। चुनावी हिंसा की घटनाएं भी लगातार बढ़ती गई हैं। राजनीतिक दलों के लोक लुभावन वादों के अलावा जाति, धर्म आदि के समीकरण जिस तरह बनाए और फैलाए जाते हैं, उससे सामाजिक समरसता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। बार-बार चुनाव कराए जाने से लंबे समय तक सरकारों के कामकाज बाधित रहते हैं, क्योंकि सरकारी अमला चुनाव संपन कराने की ज़िम्मेदारी में जुट जाता है। चुनावों पर होने वाला ख़र्च सरकारी ख़जाने पर बुरा असर डालता है, जिससे कई विकास परियोजनाओं के रास्ते में अवरोध पैदा होता है। इस तरह लोकतंत्र का उत्सव कहा जाने वाला चुनाव परेशानियों का सबब बन जाता है। इस लिहाज़ के साथ चुनाव कराना और पांच वर्ष में एक बार चुनाव कराना सभी तरह से हितकारी साबित होगा। मगर प्रश्न है कि मध्यावधि चुनाव की स्थितियों से कैसे निपटा जा सकता है।

## सम्मान की गूँज

देश की मज़बूती के लिए देश की कारगर प्रतिभाओं का सम्मान ज़रूरी है, ताकि समाज में आचरण और कर्म का एक आदर्श बना रहे। इस वर्ष देश की 128 विभूतियों को पद्म सम्मान दिए गए। जिनमें से चार विभूतियों को पद्म विभूषण के लिए पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, संगीतज्ञ प्रभा अत्रे के साथ ही गीता प्रेस के पूर्व अध्यक्ष राधेश्याम खेमका को भी दिया गया सम्मान स्वागत योग्य हैं। 17 विभूतियों को पद्म भूषण और 107 को पद्मश्री की घोषणा हुई है। सीईओ सुंदर पिचई से लेकर अभिनेता विक्टर बनर्जी तक एक से बढ़कर एक हस्तियां हैं, जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सरकार ने इस बार भी किसी को भारत रत्न देने की घोषणा नहीं की है, तो कोई अचरज की बात नहीं, बल्कि यह दुखद संकेत भी है कि अपने देश में सम्मान भी विवाद का विषय हुआ करते है। सम्मान की ख़ुशी के साथ छटांक भर दुख या नाराज़गी भी हर बार आ ही जाती है।

ग़ौर करने की बात है कि सीपीएम नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहे बुद्धदेबव भटट्ाचार्य समेत तीन हस्तियों ने सम्मान लेने से मना कर दिया है। यह संयोग ही है कि ये तीनों हस्तियां पश्चिम बंगाल से आती हैं। लगता है, वामपंथी नेता बुद्धदेव भट्टाचार्य ने राजनीतिक मतभेद की वजह से ही सम्मान लेने से मना किया है। राजनीतिक पार्टियां तो सत्ता में आती जाती रहती हैं, दस्तावेज़ों पर तो यही लिखा मिलता है कि फलां वर्ष में फलां विभूति को फलां पद्म सम्मान मिला था। राजनीतिक मतभेद अपनी जगह है, सम्मान लेने के बाद भी वह जारी रह सकता है। इस बार कांग्रेस के दिग्गज नेता गुलाम नबी आज़ाद को पद्म भूषण देने की घोषणा हुई तो ज़रूरी नहीं कि इस अवसर की राजनीति के लिए भी लाभ लिया जाए। अफसोस, व्यंग्य में ही सही, कांग्रेस के एक नेता ने उन्हें गुलाम के बजाय आज़ाद रहने की नसीहत दी है। हालांकि, अनेक कांग्रेस नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। अपने किसी नेता के सम्मान पर कम से कम किसी पार्टी के अंदर विवाद नहीं होना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद को दिया गया सम्मान, एक ऐसे नेता का सम्मान है, जो अपनी लोकतांत्रिक शालीनता से हर जगह व्यावहारिक पैठ रखते हैं।

दो अन्य विभूतियों ने भी पद्म सम्मान ठुकराया है। तबला वादक पंडित अनिंदो चटर्जी और संगीतज्ञ संध्या मुखोपाध्याय के दुख को पूरी संवेदना से समझना चाहिए। अनिंदो को सरकार से बड़े सम्मान की आशा थी, तो सरकार इस पर पहले भी बात कर सकती थी। घोषणा के बाद किसी के इंकार से बनने वाली अपमानजनक स्थिति से बचना ज़रूरी है। पद्म सम्मान कोई राजनीतिक पार्टी अपने बैनर तले नहीं देती है, सम्मान के साथ भारत सरकार की प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। यह अधिकारियों के स्तर पर कमी है कि वे विभूतियों से आवश्यक संवाद भी नहीं बना पा रहे हैं। संगीतज्ञ 90 वर्षीया संध्या मुखोपाध्याय ने सम्मान ठुकराते हुए कहा कि 74 वर्ष के लंबे कैरियर के बाद अगर सरकार को लगता है कि वह पद्मश्री के लायक़ हैं, तो उन्हें यह सम्मान नहीं चाहिए। वाक़ई यह स्थिति नहीं बननी चाहिए थी, इससे एक ख़राब संदेश गया है। सम्मान देते हुए सरकारों को पूरी संवेदना और पारदर्शिता के साथ तमाम पहलुओं पर विचार करना चाहिए, ताकि प्रादेशिक या राष्ट्रीय सम्मान किसी को अपमान की तरह न महसूस हो।

## वायरस के नए स्वरूप: बढ़ता ख़तरा

कोरोना अभी हम पूरी तरह उभरे भी नहीं थे कि अब हर दूसरे तीसरे माह हमें सुनने को मिल रहा है कि कोरोना का एक ओर स्वरूप आ गया, ये बेशक दिल दहला देने वाली स्थिति है। हाल में आया सरकारी आंकड़ा बता रहा है, कि महामारी की शुरुआत से अब तक देश में चार करोड़ से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। तईस जून 2021 तक संक्रमितों की संख्या तीन करोड़ के पार निकल चुकी थी। अब यह चार करोड़ से ऊपर है। यानि छह माह में एक करोड़ से ज़्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ गए। रोज़ाना संक्रमितों की संख्या अभी भी तीन लाख के करीब बनी हुई है। संक्रमण में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कोरोना से अब तक मारे गए लोगों का आंकड़ा चार लाख नब्बे हज़ार से ज़्यादा हो गया है। कुछ दिनों में यह आंकड़ा पांच लाख को छू सकता है। हालांकि ग़ैर सरकारी आंकड़े इससे गई गुना ज़्यादा हे यों एक

**बार-बार प्रश्न घूम फिर कर वहीं आ जा रहा है कि बचाव कैसे हो? अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो महामारी से पिंड नहीं छूटने वाला। एकाध सप्ताह में कभी मामले गिरने लगते हैं तो लगात है कि अब मुक्ति मिली। पर फिर अचानक बढ़ते संक्रमण और मौतों के मामले चिंता बढ़ा देते हैं। अकेले केरल में पचपन हजार से ज़्यादा मामले एक दिन में मिलना कोई कम गंभीर बात नहीं है। महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडू की हालत भी कमोबेश ऐसी ही है।**

बाक़ी पेज 11 पर

**ज़रूरी ऐलान**

आपकी ख़रीदारी अवधि पते की चिट पर अंकित है। अवधि की समाप्ति से पूर्व रक़म भेजने की कृपा करें।

**रक़म भेजने के तरीक़े:-**

❶ मनीआर्डर द्वारा ❷ Paytm या PhonePe द्वारा 9811198820 पर
SHANTI MISSION
❸ ऑनलाइन हेतु बैंक खाते का विवरण
SBI A/c 10310541455
Branch: Indraprastha Estate
IFS Code: SBIN0001187

**ख़रीदारी चन्दा**

| | |
|---|---|
| वार्षिक | Rs.130/- |
| 6 महीने के लिए | Rs.70/- |
| एक प्रति | Rs.3/- |

जानकारी के लिये सम्पर्क करें
साप्ताहिक
**शांति मिशन**
1, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002
फोन : 011-23311455

अपने प्रिय अख़बार साप्ताहिक शांति मिशन को इंटरनेट पर देखने के लिये लॉगऑन करें:
www.aljamiat.in —— www.jahazimedia.com
Mob. 9811198820 — E-mail: Shantimissionweekly@gmail.com

जमीअत ट्रस्ट सोसायटी की तरफ से मुद्रक, प्रकाशक शकील अहमद सैयद ने शेरवानी आर्ट प्रिंटर्स, 1480, क़ासिमजान स्ट्रीट, बल्लीमारान, दिल्ली-6 से छपवाकर मदनी हाल, न. 1, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित किया। संपादक:- मोहम्मद सालिम, फोन:- 23311455, 23317729, फैक्स:- 23316173